RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ.. सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-03, अंक - 24 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 18 मार्च 2021 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नही है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है।

बिल गेट्स

दस दिन पुर्व जन्म देने वाली मां तीन दिन से लापता का शव दूसरे के मकान की कबली में मिला

शव के बदबु मारने के बाद ग्रामिणों की सुचना पर लापता महिला का हुआ खुलासा, हत्या का मामला दर्ज

माही की गूंज, कुशलगढ़ (राज.)

कुशलगढ़ क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लापता महिला का शव नागदा बड़ी गांव में मंगलवार सुबह एक घर के अंदर अनाज भरने की कबली में मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त गांव की ही शिल्पा पति मोहन मईडा (25) के रूप में हुई। ग्रामीणों के अनुसार महिला 3 दिन से घर से लापता थी, सोमवार को ही पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कुशलगढ़ थाने में दर्ज कराई थी, महिला के परिजन एवं ग्रामीण तलाश में जुटे हुए थे। इस बीच मृतका का शव उसके घर के सामने राउमावि नागदा परिसर मे स्थित राजिया मईडा के घर के अंदर अनाज भरने की कबली मे मिला। हालाकि शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नही है, लेकिन शव दुसरे के घर मे अनाज भरने की कबली में मिलने से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने से प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है।

मकान जिसमे महिला का शव मिला।

घर से बदबू आई, तो पुलिस को दी सूचना

बदबू आने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिस पर सीआई प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बांसवाडा से डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शव तीन दिन पुराना होने से दुर्गंध के कारण नगरपालिका के सफाईकर्मीयो की मदद से कबली सहित कुशलगढ मोर्चरी मे रखवाया।

मृतका शिल्पा।

बता दे कि, मृतका का विवाह करीब 5 वर्ष पूर्व हुआ था, दो बच्चे पहले से है, इसी बीच 10 दिन पूर्व ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। जानकारी अनुसार जिस घर में महिला का शव मिला उसके मालिक राजिया का पुत्र और उसकी पत्नी पिछले कई दिनों से गुजरात मजदूरी करने गए हुए हैं। राजिया का पुत्र विनोद 2 दिन पूर्व ही उसकी साली की शादी होने से घर आया था और जिस दिन से महिला घर से गायब है उसी दिन से राजिया का पुत्र भी गायब था। थाना अधिकारी ने बताया कि, वैसे तो शव पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं है, परंतु शव दूसरे के घर में मिलने से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। महिला के पति मोहन ने विनोद पिता राजिया मईडा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है।

जानकारी अनुसार मंगलवार को राजिया के घर से

मौके पर जांच करती डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम।

महिला की शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई, पुलिस ने जांच में जिलाध्यक्ष को किया आरोपो से मुक्त

पीड़िता ने प्रदेश अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर की जिलाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

माही की गूंज झाबुआ, संजय भटेवरा

पिछले दिनों भाजपा की राजनीति में आया भूचाल अब भी शांत होता नही दिखाई दे रहा है। एक और पुलिस ने मामले की जांच में भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक को क्लीन चिट दे दी है, वहीं महिला अभी भी अपनी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए तटष्थ है और पिछले दस दिनों में मामला सीधे प्रदेश स्तर पर पहुंच गया। विगत दिनों रतलाम दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को महिला ने रतलाम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आवेदन दिया, वहीं कुछ दिन बाद ही शनिवार को महिला ने मुख्यमंत्री के पास भोपाल पहुंचकर जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि मुख्यमंत्री से मुलाकात नही हुई लेकिन उनके पीए ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जांच में महिला पर ही पुलिस ने लगा दिए व्यवसाय के लिए लाभ उठाने के आरोप

मामले में हुई जांच के बारे में पुलिस खुल कर कुछ नही बोल रही है, लेकिन पीड़ित महिला द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के जवाब में पुलिस की और से जो जवाब दिया गया, उसमे साफ-साफबताया गया कि, महिला द्वारा लगाए गए आरोपो में सत्यता नही पाई गई और मामले में कोई अपराध नही बनता। पुलिस ने महिला द्वारा की गई शिकायत का बिंदुवार जवाब देते हुए ये भी बताया कि, महिला अपने व्यवसाय में लाभ लेने के उद्देश्य से भाजपा जिलाध्यक्ष पर दबाव बना रही थी। पुलिस ने जांच में भाजपा के कुछ नेताओं के भी बयान दर्ज किए, जिनसे क्या उम्मीद की जा सकती है ये कहने की आवश्यकता नही है। पुलिस की और से दिए गए जवाब के बाद महिला द्वारा की गई शिकायत को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पीड़िता द्वारा शिकायत के ऐवज में दिए जवाब से असंतुष्ट होने के बाद अब सीएम आवास पहुंचकर शिकायत की गई।

महिला की शिकायत झूठी, तो पुलिस शिकायतकर्ता पर करेगी क्या कार्रवाई?

पुलिस जांच के हिसाब से महिला द्वारा शिकायत करने का उद्देश्य जिलाध्यक्ष की छवि धूमिल करना बताया गया है, मतलब पुलिस अब महिला पर झूठी शिकायत दर्ज करने और भाजपा के चरित्रवान नेता लक्ष्मणसिंह नायक की छवि धूमिल करने का प्रकरण बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई महिला ऐसे ईमानदार और बेदाग छवि वाले नेता पर इस प्रकार के झूठे ओर गम्भीर आरोप नही लगा सके।

पीड़िता के पति ने कहा कोर्ट जाऊंगा, पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में कर रही है काम

उधर पुलिस से न्याय नही मिलने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व व सरकार के सामने अपनी बात पीड़िता और उसके पति ने रख दी है, लेकिन कोई परिणाम पीड़िता के पक्ष में नही आए है। महिला और उसके पति का कहना है कि, यदि यहां से न्याय नही मिला तो न्यायालय में जाएंगे, वही महिला के पति ने कहा है कि, पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है।

बीएसपी विधायक के पति की सूचना देने वाले को 30 हजार का इनाम देगी पुलिस

नई दिल्ली, एजेंसी। मध्य प्रदेश पुलिस ने बुधवार को 2019 की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ईनाम की घोषणा की है। इस हत्या में आरोपी राज्य की बसपा विधायक के पति की गिरफ्तारी के लिए 30 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। दरअसल, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी हैं। रामबाई सिंह राज्य के दमोह जिले के पथरिया से विधायक हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को कहा कि, मामले के तथ्य बताते हैं कि 15 मार्च, 2019 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जांच अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को गंभीरता से लेने के बाद, पुलिस ने गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

सागर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा ने बताया, कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए 30 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन माहेश्वरी भी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के प्रयासों के लिए पिछले दो दिनों से दमोह में ही हैं।

जब कुछ कर ही नहीं सकते तो बैठकें करते क्यों हो ?

आपदा प्रबंधन समिति की बैठक यानि 'ढाक के तीन पात'

माही की गूंज,झाबुआ। मुजम्मील मंसूरी

जब किसी नियम को लागू करना संभव न हो या उसे लागू करने और अमल करवाने की ताकत न हो तो उस पर बैठकें करना और बेमतलब की चिल्लपो करना 'अंगूठे को कुतुब मीनार व हथेली में दिल्ली दिखाने' जैसा ही लगता है। सिर्फ बैठक करने से ही समस्या का निदान अगर निकलता होता तो यह जिला अब तक स्वर्ग की दहलीज को कम से कम बन ही जाता। विडंबना यह है कि जिले की राजनीतिक लचरता और अफसर शाही का रौब-रूबाब इस जिले को आगे ले जाना ही नही चाहता। प्रशासन की जादूगरी सिर्फ कागजों पर ही नजर आती है, धरातल पर स्थिति 'ढाक के तीन पात' सी आज भी वही है। जिले की आज जो भी स्थिति है उसमें एक हाथ और भी है, जिसे प्रशासन ने अपना दुमछल्ला बनाकर नाम दिया है 'समाजसेवी'। दुमछल्लों के इस गिरोह को एक लड़ी में पिरोते हुए प्रशासन ने जिला आपदा प्रबंधन की समिति बना डाली। अब जब भी जरूरत पड़ती प्रशासन अपने हिसाब से अपनी दुमछल्ली टीम को बुलाकर बैठक करता, हंसी ठिठोली करता, कुछ सुनता-सुनाता, नाश्ता कराता और सुझावों के नाम पर बकवास बाजी कर दुमछल्लों को रवाना कर देता। एक बड़ी विडंबना यह है कि आज तक इन बैठकों की सार्थकता साबित नहीं हो पाई। बैठक में लिए गए निर्णय रूपी परिदे के पंख इतने विशाल है कि उसे कभी जमीन पर उतरता देखा ही नहीं गया। हा यदा-कदा इतना जरूरी होता कि वह जमीन पर सिर्फ इतने समय के लिए आता जितने समय में घोड़ा अपनी थकान मिटाने के लिए एक लौट मार कर खड़ा हो जाता। इसी तरह इन बैठकों में लिए गए निर्णय भी कुछ समय में ही हवा हो जाते।

मंगलवार को भी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, पूरे कोरोना काल में इस तरह की बैठकें आयोजित होती रही है। कई निर्णय व फैसले इन बैठकों में हुए, लेकिन वह जमीन पर कितने उतरे यह तो शायद प्रशासन भी न बता पाए। हमारी नजर से यह 'जीरो बटे सन्नाटा' ही साबित हुए है।

मंगलवार को आयोजित यह बैठक 22 मार्च से शुरू हो रहे आदिवासी समाज के पर्व भगोरियों में कोरोना गाइडलाइन के पालन कराने और आयोजन की रूप रेखा तैयार करने को लेकर लिए किय गया। इस बैठक में मास्क पहनने के नियम को लेकर

बहस हुई। दुकानदारों को दुकान के बाहर रस्सियां बांधे या दूसरा कोई अवरोध रखे ताकि सोश्यल डिस्टेंस का पालन हो सके। दुकान पर मास्क पहनकर नहीं आने वालों को मास्क उपलब्ध कराएं। दुकानदार खुद भी मास्क का उपयोग करें। सोश्यल डिस्टेंस के लिए गोले बनाएं। पालन नहीं करने पर दुकानदार को 500 रुपये का दंड तथा ग्राहकों के पालन नहीं करने पर 100 रुपये का दंड रखा गया। रखे गए इस जुर्माने पर व्यापारियों ने आपत्ती दर्ज कराते हुए इसे कम करने की बात कही, लेकिन कलेक्टर ने इसे कम करने से मना कर दिया। बल्कि इसके उलट उन्होने कहा कि अगर नियम नहीं माना तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। कलेक्टर साहब का यह कहना था कि इतना दंड रहेगा तो लोग मास्क पहनेंगे। बैठक में झुले-चकरी भगोरिये में नहीं लगाने की बात रखी गई, तो किसी ने झूले-चकरी में कम लोगों को सोश्यल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाने की बात कही, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। तर्क यह था कि ऐसा करने पर छोटे झूला व्यापारियों को नुकसान होगा।

दुसरा मुद्दा बैठक में यह रहा कि भगोरिये में ढोल-मांदल के साथ आने वाले समूहों के बीच दूरी तय की जाए। प्रशासन जो जवाब इस बात को लेकर था वह भी आश्चर्य चकित करने वाला था। प्रशासन का कहना था कि इस कार्य को करने के लिए प्रशासन और पुलिस के पास इतना अमला नहीं है कि ऐसा किया जा सके। पूरे मेला स्थल पर निगरानी रखना मुश्किल है।

जब बैठक में यातायात को लेकर सवाल उठा और ओवर लोडिंग की बात हुई तो कलेक्टर ने सभी एसडीएम को इसका खास ध्यान रखने के निर्देश दिए। साहब का कहना था कि यह दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। बैठक में अधिकारियों द्वारा जब यह बात कही गई कि समझाने के बाद भी कई लोग मास्क नहीं पहनते, अस्पताल में भी आ जाते है। तो कलेक्टर का कहना था कि अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मास्क पहनने से मना करता है तो उसे वापस लौटा दिया जाए।

इसके अलावा बैठक में कई मुद्दों पर बहस हुई, लेकिन कोई भी बात किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। बैठक में मौजूद कई लोग आयोजन को छोटे स्तर पर करने के पक्ष में थे तो कई इससे सहमत नहीं हुए। बात में बात तो यह भी निकल कर आई कि जब पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में लाखों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है तो आदिवासी पर्व को रोकना कहां तक सही है। हालांकि प्रशासन ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भगोरियों को रोकने का कोई विचार नहीं है।

इतने गंभीर मुद्दे पर हुई इस बैठक का फैसला, सारांश, निचौड़ क्या निकला यह किसी को पता नहीं? मतलब सीधा -सीधा है कि प्रशासन जिले में आयोजित होने वाले भगोरिया मेलों में कोरोना गाइड लाइन का पालन करवाने में असमर्थ है। आयोजन को रोकने का कोई विचार नहीं है। प्रशासन का सीधा सा मतलब यह भी हो सकता है कि कोरोना से हमें कोई जंग नहीं लड़ना है या फिर कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। कुल मिलाकर कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई दुमछल्लों की इस बैठक में नतीजा वही 'ढाक के तीन पात रहा'।

हमने पिछले कई दशकों से भगोरिया मेले देखें है। उसमें उमड़ती भीड़ देखी है। उसमें उमड़ता उल्लास, मद मस्ती, अल्हड़पन देखा है। स्थितियां यह होती है कि कोई किसी के बस में नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वक्त और कोरोना की दरकार है कि कुछ तो किया जाना चाहिया। प्रशासन आपका ख्याल नहीं रख सकता। आपको और हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा। त्यौहार का उल्लास भी कम न हो और कोरोना से लड़ाई भी जारी रहे। हालांकि यह परिकल्पना माल ही है। कलेक्टर साहब ने यह देखा हो या न देखा हो मगर उनके अधिनस्तों ने तो यह सब कुछ बरसों से देखा है। मगर इतने अरसे से देखे जा रहे भगोरियों के अनुभव का किसी को कोई फायदा इस स्थिति में देखने को नहीं मिल रहा है।

हालांकि आपदा प्रबंधन की इस बैठक में भगोरिया में अपनी दुकान सड़क पर लगाने वाला एक भी व्यापारी नहीं था। जिन दुकानदारों से सोश्यल डिस्टेंसिंग , मास्क व जुर्माने की बात कलेक्टर ने कही है, यह सिर्फ स्थाई दुकानदारों पर ही लागू हो सकता है। भगोरियों में जो दुकानें लगती है उन पर इन नियमों का पालन हो पाना नामुमकिन ही है। प्रशासन को बैठकों के नाम पर इस तरह के ढकोसले करना शोभा नहीं देता। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो बैठकें करते क्यों हो।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूपी जैसे राज्यों में बर्बाद हो रही कोरोना वैक्सीन- पीएम मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना वैक्सीनेशन और संक्रमण में इजाफे को लेकर मीटिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों में दवा की बर्बादी को लेकर राज्यों को नसीहत दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 10 फीसदी से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हुई है, इसके अलावा यूपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि, आखिर दवा की बर्बादी क्यों हो रही है? हर शाम को दवा की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्रो-एक्टिव लोगों से संपर्क करना चाहिए, ताकि कोई बर्बादी न हो सके। ये ही नहीं पीएम ने कहा, यह चिंता की बात है कि आखिर कुछ इलाकों में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन कम क्यों हो गया है? मेरे ख्याल से यह समय गुड गवर्नेंस को परखने का है। हमारा आत्मविश्वास अतिआत्मविश्वास में तब्दील नहीं होना चाहिए।

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे भारत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि, भारत में 96 फीसदी लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। कई राज्यों में कोरोना के केसों में कमी आई थी और अब फिर इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हुआ है। देश के 70 जिलों में कोरोना की संख्या में 150 फीसदी का इजाफा हुआ है। यदि हमने दूसरी लहर को तुरंत नहीं रोका तो फिर मुश्किलों का सामना करना होगा।

कौतूहलः भैंस ने सफेद बछड़े को दिया जन्म

माही की गूंज आम्बुआ, मयंक विश्वकर्मा

भैंस अमुमन काली व भुरी होती है तथा दूध सफेद देती है, यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। मगर जब भैंस सफेद वह भी बिल्कुल गाय के बछड़े जैसा बछड़े को जन्म देती है तो आश्चर्य तो होगा ही। आम्बुआ मस्जिद मोहल्ले में रहने वाले पशु पालक शकील सफीक मोहम्मद कुरैशी के घर यह कौतूहल भरा कुदरती कारनामा प्रकृति के विपरीत देखने को मिला। शकील सफीक मोहम्मद कुरैशी की एक भैंस ने एक स्वस्थ व सफेद बछड़े को जन्म दिया है। उक्त भैंस के सफेद बछड़े को जन्म देने की बात सुनकर हर कोई कौतूहल के कारण भैंस पालक के घर पर देखने वालों का मजमा लग रहा है। देखने पर यह भैंस की बजाए गाय का बछड़ा ही दिखाई देता है, कुदरत के इस अद्भुत नजारे को लोग देखने आ रहे हैं।

मामला: झकनावदा चौकी के ग्राम बिजौरी में हुई महिला की मौत का

हत्या या आत्महत्या: पुलिस ने मामले को लाकर खड़ा किया संदेह के घेरे में

माही की गूंज, झाबुआ।

कोई भी गुनेहगार हो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा मिले यह हम कभी नहीं चाहते। परंतु पुलिस कई मामलों में निष्पक्ष जांच के पूर्व ही मामले को संदेहास्पद स्थिति में लाकर खड़ा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। कुछ ऐसा ही मामला झकनावदा चौकी के ग्राम बिजोरी का है, जहां रमेश बघेल की पत्नी की मौत, हत्या या आत्महत्या है निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाता, परंतु पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी रही की पूरे मामले को संदेहास्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया।

उक्त मामले में लड़की के पियर पक्ष के परिवार ने लड़की पर गलत आरोप लगाकर प्रताड़ित कर उसके पति द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया है और मामले में चौकी में बयान होने के साथ ही मान्य न्यायालय पेटलावद में 164 के तहत मृत महिला के दो नाबालिक बच्चों ने भी पिता के द्वारा ही उनकी मां को मौत के घाट उतारा है के बयान दे चुके हैं। उक्त मामले को पूर्ण रूप से संदेहास्पद रूप में लाकर खड़े करने का प्रयास पुलिस का रहा है।

माही की गूंज ने भी उक्त मामले को हमारे पिछले अंक में प्रकाशित किया है। वही मृत महिला के पति रमेश ने भी एसडीओपी पेटलावद एवं पुलिस अधीक्षक को लिखित रिपोर्ट दर्ज कर पवन चौधरी कुमावत निवासी फुलगामड़ी (सरदारपुर) तथा एक अज्ञात महिला पर उसकी पत्नी को ब्लैकमेल व डरा धमकाकर प्रताड़ित किया गया, जिस पर उसकी पत्नी ने मौत को गले लगा लिया की रिपोर्ट दर्ज की। वहीं पति रमेश ने उसकी ससुराल वालों के विरुद्ध भी अपनी रिपोर्ट में रुपए नहीं देने के ऐवज में उसे झूठे प्रकरण में फसाने की कोशिश की

जा रही है कि रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही कुछ रिकॉर्डिंग व पवन चौधरी एवं अज्ञात महिला की मोबाइल डिटेल के साथ अपने बचाव पक्ष में कुछ तत्थ पुलिस को दिए। वही लड़की के पियर पक्ष ने रमेश के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने पर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी।

पुलिस ने इस तरह से किया मामले को संदेहास्पद

सर्वप्रथम पुलिस द्वारा लड़की पक्ष यानी रमेश के ससुराल पक्ष को संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया, वही जब पुलिस चौकी झकनावदा में लड़की के माता-पिता व भाई उनके नातिन को बयान हेतु झकनावदा चौकी पर ले गए तो, जिसके विरोध में बयान दिए गए उसी पिता रमेश को बयान देते समय चौकी कक्ष में बच्चों के पास खड़ा किया गया?

दूसरा जब पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टिया कहीं न कहीं यह सिद्ध हो रहा था कि, महिला ने आत्महत्या की है व रमेश गुनेहगार नहीं है तो, आत्महत्या का कारण रमेश द्वारा की गई रिपोर्ट पर पवन चौधरी एवं अज्ञात महिला के विरुद्ध अपनी जांच का रूख ले जाकर जांच करने का प्रयास क्यों नहीं किया?

वहीं तीसरा जब मृतका के पिता परिवार ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो पुलिस ने शिकायत लेने का दबाव क्यों बनाया? और फिर शिकायत सीएम हेल्पलाइन से लेने के ऐवज में संधिकर उनके पक्ष में की गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का हवाला देकर सीएम हेल्पलाइन से शिकायत को परिवार द्वारा लेने पर कार्रवाई के नाम पर 164 के बयान करवाना?

यह सारी बाते पुलिस की कार्यप्रणाली के चलते मामले को संदेहास्पद स्थिति में लाकर खड़ा करती है और आखिर में मृतिका महिला की मौत का कारण कौन है, यह पुलिस स्पष्ट नहीं कर पा रही है। सवाल यह उठता है कि जब पुलिस की कार्यप्रणाली सही है तो सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत में पुलिस को निष्पक्ष जांचकर मामले की तह तक पहुंचकर अपना प्रतिवेदन पेश करती व मामले में अगर रमेश दोषी नहीं होता तो स्वतः ही वह शिकायत निराधार हो जाती।

पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर इन बिंदुओं पर भी करें निष्पक्ष जांच

* रमेश द्वारा जो-जो रिकॉर्डिंग पेश की गई जिसमें उसके ससुराल पक्ष ने भी गलती होने पर लड़की मरे तो मरने दो की बात कही है, वह रिकॉर्डिंग षड्यंत्र रूप से योजनाबद्ध तरीके से तो नहीं की गई और पत्नी को आदेश में आकर कहीं मौत के घाट तो नहीं उतारा गया?
* पवन चौधरी किस नियत से महिला से बात करता था व किस तरह से प्रताड़ित किया गया, साथ ही वह अज्ञात महिला कौन थी जिसने मृतका की मौत के दिन फोन कर धमकाया जिस पर महिला को आत्महत्या करना पड़ी?
* जब पवन चौधरी गुनेहगार नहीं है तो महिला की मौत के बाद आखिर क्यों अपने मोबाइल नंबर 9098135953, 8435354573 को बंद कर फरार हो गया।
* मृतका के पियर पक्ष द्वारा क्या वास्तविकता में बच्चों को बरगलाकर बयान दिलवाए जा रहे हैं या वास्तविक घटना को बच्चे अपने बयान में बता रहे है? आदि की उच्चस्तरिय जांच कर मामले का खुलासा करना आवश्यक है।

अगर पुलिस उच्चस्तरीय जांच उक्त मामले में नहीं कर मामले को रफा-दफा करती है तो हो सकता है असली गुनहगार बाहर ही घूमेगा। इसलिए पुलिस अधीक्षक को मामले में उच्चस्तरीय जांच करवाकर मामले का खुलासा करना आवश्यक है।

कलेक्टर ने रामा तहसील के विभिन्न ग्रामों का किया भ्रमण

आयुष्मान भारत निरामय योजना की प्रगति की समीक्षा

माही की गूंज, झाबुआ। कलेक्टर रोहित सिंह ने रामा तहसील के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर मिशन चिरंजीवी आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा की और इस योजना के तहत युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिए। सिंह ने ग्राम देवझीरी पण्डा, ग्राम पंचायत छापरी, कालीदेवी में मिशन चिरंजीवी आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा की और सचिव तथा रोजगार सहायक को शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही पटवारी तथा कोटवार को भी इस कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए। सिंह ने कहा कि समय पर लक्ष्य पूर्ण करने पर सीएससी को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहन कनास, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग प्रशांत आर्या, तहसीलदार प्रवीण ओहरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एमएल टॉक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कांग्रेस निकालेगी 20 मार्च को तिरंगा यात्रा

माही की गूंज, झाबुआ। मध्य प्रदेश के इतिहास में वह काला दिन जीस दिन कमल नाथ ने इस्तीफा दिया था। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेताओं ने येन-केन प्रकरण देश के संविधान, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, प्रदत्त मतदाताओं द्वारा चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था। इसी परिपेक्ष में प्रदेश व जिले की जनता जनार्दन को भाजपा के कृत्यों से अवगत कराने के उद्देश्य स्वरूप तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो 20 मार्च को सुबह 11 बजे स्थानीय जिला कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ होकर बस स्टैंड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर उन्हें माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा का समापन किया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता, कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता साबिर फिरवेने ने बताया कि आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रभारी अरविंद जोशी, विधायक कांतिलाल भूरिया, वीरसिंह भूरिया, वालसिंह मेड़ा, पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा, कार्यवाहक अध्यक्ष हेमचंद डामोर, रूपसिंह डामोर, नगर पालिका अध्यक्ष मनु डोडियार तथा जिले के समस्त ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस, अध्यक्ष विशेष रुप से भाग लेंगे।

मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर काकड़ डोरा की रस्म अदा की गई

माही की गूंज, झाबुआ।

शहर के छोटे तालाब स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शिव प्रिया महिला मंडल द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में नौ दिवसीय आयोजन किए गए। जिसमें महिला मंडल की सभी सदस्याओं ने विधि-विधान पूर्वक मनकामेश्वर महादेवजी और जगत जननी मां पार्वतीजी की विवाह रस्म संपन्न करवाई। जिसके तहत मंगलवार को काकड़ डोरा की रस्म भी अदा की गई। आयोजक शिव प्रिया महिला मंडल ने नौ दिवसीय आयोजन को सफल बनाने में लाभार्थियों, भक्तजनों और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

विवाह रस्मों के अंतर्गत शिव प्रिया महिला मंडल ने मंदिर में काकड़ डोरा की रस्म भी अदा करवाई। जिसमें दूल्हा-दुल्हन के रूप में देवेन्द्र पूरी तथा रेखा गोस्वामी ने रस्म में भाग लिया। उन्हें कन्यादान में भक्तों द्वारा साड़ियां, पेंट-शर्ट, नगदी, चांदी की बिछुड़ी, सोने का मंगलसूत्र तथा बाली, चांदी की पायजब, बर्तन इत्यादि भेंट किए गए। यह आयोजन भी पूरे उत्साह के साथ आयोजक महिला मंडल की ओर से संपन्न करवाया गया।

सभी का माना आभार

सभी आयोजनों को सफल बनाने के लिए शिव प्रिया महिला मंडल की रूक्मणी वर्मा, अनिला बेस, रजनी पाटीदार, सुनिता गेहलोत, शोभा राठौर, टीना गोतम, कमला सोलंकी, लता चौहान, गीता पाटीदार, सुमित्रा चौहान, रानी पांडे, भावना टेलर, आरती मिश्रा, शिवकुमारी सांकला, माया पंवार, आशा राशिनकर, राधा पटेल, विनीता टेलर, राजेश्री परमार, शालिनी सक्सेना, हेमा परमार, साधना कनौजे, सीमा चौहान, आरती मिश्रा, चंद्रकांता कुशवाह, ममता जादौन, मधु पंवार, सुनिता सिसौदिया, सावित्री गौतम आदि ने लाभार्थियों, भक्तजनों, मनकामेश्वर महादेव मंदिर समिति, मनकामेश्वर महादेव मंदिर महिला मंडल, सभी भक्तों और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।

आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए

माही की गूंज, झाबुआ। मिशन चिरंजीवी आयुष्मान भारत निरामय योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक मंगलवार को कालीदेवी में स्थित जनपद पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर रोहित सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सिंह ने इस योजना की प्रगति की पंचायतवार समीक्षा की और इस कार्य में लगे मैदानी अमले को निर्देश दिए हैं कि वे आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने का कार्य तीन दिन में पूर्ण करे। जिन पंचायतों में यह कार्य पूर्ण होने पर अन्य ग्राम पंचायतों में कार्ड बनाने का कार्य प्रारम्भ करें। ताकि रामा जनपद पंचायत जिले में कार्ड बनाने के मामले में अग्रणी आ सके। कलेक्टर सिंह ने ग्राम पंचायत धामन्दा के रोजगार सहायक की बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर सेवा से पृथक करने, छापरी कालीदेवी के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एमएल टॉक, तहसीलदार प्रवीण ओहरिया, बीएमओ, समस्त उपयंत्री, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने सीएमएचओ से की मुलाकात

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के केसों को लेकर तथा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लेकर चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम तथा कोविड से रोकथाम हेतु चरणबद्ध लगाए जा रहे वैक्सीन कार्य संबंधी जानकारी हेतु मंगलवार को भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपालसिंह ठाकुर से मिला और उनसे उक्त विषयों संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

ज्ञातव्य रहे कि वर्तमान सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से कोविड से रोकथाम हेतु जिले में क्षेत्रवार प्रभारियों की नियुक्तियां की गई है। जिनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को इस जानलेवा महामारी के संबंध में जानकारी देने के साथ इसके लक्षण और बचाव संबंधी भी प्रयास किए जा रहे है। इसी क्रम में जिला भाजपा की ओर से बनाए गए कोविड जिला प्रभारी भाजयुमो जिलाध्यक्ष भानु भूरिया, नगर प्रभारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय पोरवाल, भाजपा मंडल झाबुआ के अध्यक्ष अंकुर पाठक, मंडल महामंत्री जुवानसिंह गुंडिया, देवझिरी मंडल अध्यक्ष सुरभानसिंह गुंडिया, सांसद प्रतिनिधि मनोज अरोरा, नगर कोषाध्यक्ष नरेन्द्र राठौरिया, भाजपा मंडल झाबुआ पदाधिकारी अजय डामोर, निजा चिकित्सा संघ से डॉ. अरवन्दि दातला, स्वीट गोस्वामी आदि द्वारा सीएमएचओ डॉ. ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें भाजपा की ओर से इस महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया।

सीएमएचओ डॉ. ठाकुर से चर्चा करते हुए भाजपा पदाधिकारीगण।

सहयोग की अपेक्षा की

चर्चा के दौरान ही सीएमचओ डॉ. ठाकुर ने उपस्थित जिला भाजपा तथा नगर मंडल के पदाधिकारियों से भी इस संबंध में जिला स्वास्थ्य विभाग को सहयोग कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, इस हेतु उन्हें प्रेरित करने व उन्हें टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाने की बात कहीं। जिस पर अमल हेतु भाजपा पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया।

तेरापंथ महिला मंडल ने तपस्वियों का किया बहुमान

माही की गूंज, झाबुआ। जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल झाबुआ ने विगत वर्षों में व वर्तमान में वर्षीतप की तपस्या कर रहे सभी तपस्वीजन का बहुमान किया तथा सभी सदस्यों से सुख साता पूछते हुए, शुभकामनाएं प्रेषित की। तेरापंथ महिला मंडल सचिव हंसा गादीया ने बताया कि सोमवार को लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित तेरापंथ सभा भवन पर सभी तपस्वीजन का बहुमान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम नवकार महामंत्र का उच्चारण व जाप करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में करीब विगत 3 वर्षों से वर्षीतप कर रही तेरापंथ महिला मंडल पूर्व अध्यक्ष सुशीला कोठारी का बहुमान महिला मंडल ने शॉल ओढ़ाकर व माला भेंट कर किया। उसके बाद तपस्वी आजाद श्रीमाल, उषा कांसवा, सोनिया कोठारी, रानी कोठारी का भी बहुमान किया गया। तेरापंथ युवक परिषद के पूर्व सचिव तपस्वी वैभव पूनमचंद कोठारी का बहुमान तेरापंथ सभाअध्यक्ष मुकेश नागोरी व सुश्रावक कैलाश श्रीमाल द्वारा साहित्य भेंटकर सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह के बाद सर्व तेरापंथ समाज के श्रावक-श्राविकाओं ने तपस्या की सुख-साता जानते हुए, उनकी तप की अनुमोदना करते हुए जयकारे भी लगाएं। इसके बाद सर्व तेरापंथ समाज की महिलाओं द्वारा धार्मिक गीतों का संगान कर समस्त तपस्वी जन के तप की अनुमोदना की। कार्यक्रम का संचालन तेरापंथ महिला मंडल सचिव हंसा गादीया ने किया व आभार सभा अध्यक्ष मुकेश नागोरी ने माना।

ई-टेण्डर के माध्यम से मदिरा निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी

माही की गूंज, झाबुआ। ई-टेंडर के माध्यम से मदिरा समूह का निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी। ई-टेंडर के लिए ऑनलाईन प्रपत्र डाउनलोड तथा ई-टेंडर ऑफ़ समीट करने की तिथि 18 मार्च को दोपहर 1 बजे तक रहेगी। ई-टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि 18 मार्च 2021 को दोपहर 1.05 बजे है। निष्पादन की जाने वाली मदिरा दुकानों, एकल समूह को लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति वेबसाईट पर ई-टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ई-टेंडर से सम्बन्धित नियमों, दुकानों का विवरण, मादक द्रव्यों की खपत, ड्यूटी दर तथा अन्य आनुशांगिक शर्तों की जानकारी वेबसाईट पर तथा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला झाबुआ से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छुक टेंडरदाता को ई-टेंडर की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाईट पर कराना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

बने हुए रोड का कर दिया अनुमोदन, गूंज की खबर पर लगी मौहर

मिली भगत का मामला आया सामने, अधिकारी झाड़ रहे पल्ला, फर्जी रोड के नाम पर पैसा निकालने की है तैयारी

मौके पर बना आधा जीएसबी रोड जिसका नया निर्माण स्वीकृत किया गया, रोड के मस्टर अब तक जारी नही हुए है, रोड का एक हिस्सा बनना बाकी।

माही की गूंज पेटलावद, राकेश गेहलोत

विकास खण्ड में चल रहे मनरेगा के कार्यो में भ्रष्टाचार और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत का बड़ा मामला उजागर हुआ है। माही की गूंज ने पहले से मनरेगा के कार्यो में होने वाली धांधली का खुलासा किया था, जिसकी पुष्टि के लिए ग्राउंड लेवल तक पहुंचे तो भ्रष्टाचार का पूरा पिटारा सामने गया। जबकि अनुमोदन के लिए रुके कार्यो में फर्जी कार्य होने की जानकारी अधिकारियों को दी गई और समाचार प्रकाशित भी किए गए जिसमे कार्यो के अनुमोदन से पहले जमीनी स्तर पर कार्यो के निरीक्षण की बात कही गई थी, लेकिन अनुमोदन के पीछे कमीशन की जो बात निकल कर आ रही उसकी कही न कही पुष्टि होती नजर आ रही है। क्योंकि किसी भी कार्य के अनुमोदन से पूर्व मौका जांच नही की गई और ऑफिस की चार दिवारी के बीच बैठकर मामला नेताओ के दबाव व लेन-देन से निपटा दिया।

25 लाख का जीएसबी रोड आधा बना हुआ, फर्जी बिल और मजदूरी के नाम पर पैसे निकालने की तैयारी

बात करे मनरेगा अंतर्गत जीएसबी मार्ग की तो ग्राम पंचायत अलस्याखेड़ी में बनने वाले 24 लाख 97 हजार रूपए की लागत के जीएसबी मार्ग के निर्माण के लिए तकनीकी और प्रशासकीय आरईएस विभाग व जनपद पेटलावद द्वारा जारी की गई थी, लेकिन अनुमोदन के अभाव कार्य शुरू नही हो सका था। मार्ग की कहानी मौके पर बिल्कुल अलग है। उक्त रोड जहां से जहां तक बनना था उसमें से आधा रोड़ बना हुआ है मौके पर मोरम बिछा हुआ है। ग्रामीणों से जानकारी ली गई तो बताया कि, कुछ समय पूर्व जेसीबी के माध्यम से ग्राम पंचायत ने यहां मोरम बिछवाया थी, किसी भी मजदूर ने यहां कोई काम नही किया न ही उक्त कार्य के कोई मस्टर जारी हुए। अब मनरेगा योजना के माध्यम से उक्त मार्ग बनना बताकर राशि आहरण करने की तैयारी की जा रही है, उक्त कार्य के अनुमोदन के बाद फर्जी मस्टर और ट्रेक्टर के बील लगाकर राशि निकलने की तैयारी की जा रही है।

मामले में जब जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा की गई तो उनके जबाब भी चौंकाने वाली बात कर रहे है। आरईएस एसडीओ डीके अग्रवाल का कहना है, उन्होंने कार्य के उपयंत्री के हस्ताक्षर देखकर अपने हस्ताक्षर कर दिए और समय अभाव के कारण मौके का निरीक्षण नही किया गया।

अधिकारी के जबाब से ही पता चलता है कि, मनरेगा कार्यो के नाम पर भ्रष्ट अपना हित साधने के अलावा और कोई काम नही कर रहे है। मनरेगा जिला परियोजना अधिकारी मनोज भारस्कर जिन नियमों का हवाला देकर सांसद-विधायक के द्वारा भूमिपूजन किए कार्यो को रोक दिया था, जिनके अनुमोदन के बाद अब कार्यो को शुरू किया जाना है। जब अलस्याखेड़ी में बने हुए आधे-अधुरे रोड की जानकारी मनरेगा परियोजना अधिकारी भारस्कर को दी गई तो उनका कहना है कि, मनरेगा के ई ओर उपयंत्री से जांच करवा लेगे।

बेनकाब हो रहे चेहरे, उपयंत्री की भूमिका संदेह के घेरे में

सत्ता में बैठे कई नेताओ और अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो रहे है। जहां एक और अधिकारियों ने करोड़ो के मनरेगा के कार्य रोके तो, सत्ता में बैठे सांसद गुमान सिंह ने मनरेगा के अधिकारियो की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर लिखित शिकायत कर दी। लेकिन जैसे ही उनकी मंशा अनुसार कार्यो को हरी झंडी मिली, कार्य में अड़ंगा फसाने वाले अधिकारी फिर से ईमानदार हो गए। एक और एसडीओ आरईएस कह रहा है कि, बिना निरीक्षण के कार्यो को उपयंत्री के हस्ताक्षर के आधार पर अपनी सहमति से आगे बढ़ा दिया तो, मनरेगा परियोजना अधिकारी का कहना है कि, जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करना था। पूरे मामले में कार्य के उपयंत्री की भी भारी लापरवाही सामने आ रही है जो बिना जांच पड़ताल के स्टीमेट पर अपनी सहमति में हस्ताक्षर कर कार्य का गलत स्टीमेट बनाकर कार्य का गलत मूल्यांकन कर रहे है। अब कार्य से जुड़े अघोषित ठेकेदार जुगाड़ लगाकर फर्जी बिल और मजदूरों की हाजरी लगाकर रोड की राशि की बंदरबांट करने की जुगाड़ कर रहे है जिसमे बड़े नेताओं और अधिकारी का भी हाथ है।

नदी पुनर्जीवन के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण को देखने वाला कोई नहीं

उपयंत्री अहिरवार का भ्रष्टाचार रुकने का नाम नही ले रहा, चेक डेम ने दिलवा दी लाखो की गाड़ी, सरपंच-सचिव के भी हो रहे न्यारे-न्यारे

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बाछिखेड़ा जहां आए दिन शासकीय कार्यो में भ्रष्टाचार उजागर होते है। यहां नदी पुनर्जीवन योजना अंतर्गत बनाए जा रहे चेक डेम में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है जिसको देखने वाला कोई नही है। लाखों रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम से सरकार का उद्देश्य है कि, पानी रोकना और ग्रामीणों को रोजगार भी देना, लेकिन ग्राम पंचायत बाछिखेड़ा में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे ग्राम पंचायत निवासी ग्रामीणों को किसी प्रकार का रोजगार मिले। जिन योजनाओं के माध्यम से राशि आ रही है उसका खुला दुरुपयोग करते हुए ग्राम पंचायत बाछिखेड़ा के द्वारा कार्य अघोषित ठेकेदारो से करवाया जा रहा है।

जाहिर है कि, ग्राम पंचायत बाछिखेड़ा के सचिव मोतीलाल गरवाल और सरपंच नानुराम मुनिया और द्वारा जनपद में बैठे भ्रष्ट लोगों को अपना हिस्सा पहुंचाकर मुह बन्दकर दिया है। वही उपयंत्री अहिरवार की बात ही निराली है इनको शासकीय कार्य की गुणवत्ता से कोई लेना-देना नही है, जिसके लिए सरकार उन्हें हजारों रुपए का मासिक वेतन दे रही है। कार्य मे किस प्रकार के मटेरियल उपयोग हो रहा है इससे इनको कोई लेना-देना नहीं, चाहे जवाबदार पंचायत उसमें राखौड़े का ही उपयोग कर दे, उपयंत्री को केवल अपने कमीशन से मतलब है। चैक डेम के निर्माण को देखकर इसके घटिया निर्माण की पोल खुल रही है। कार्य मे उपयोग आने वाली रेत जो किसी नाले की लगाई जा रही हैं या तो फिर डस्ट में ही काम चलाया जा रहा है। ऐसे अनेक प्रकार से लूटने का काम चल रहा है। वहीं डेम की नींव के अंदर बड़े बोल्डर पत्थर डाले जाते हैं ताकि ठेकेदारों के द्वारा पैसे बचत हो जाए।

मिली जानकारी के अनुसार, उपयंत्री अहिरवार को अपने क्लस्टर मे होने वाले कार्यों से कोई लेना-देना नही है, उनको मात्र उनके हिस्से की राशि से मतलब है और एक चैक डेम के मूल्यांकन के लिए तय रकम की वसूली की जा रही है, जिसके बाद पंचायत और अघोषित ठेकेदार मनमाने ठंग से कार्य कर सकते है। बताया जा रहा है, साहब अभी-अभी लाखो की नई कार भी खरीद लाए है जिसमे बैठकर उपयंत्री अहीरवार एसी की हवा में बैठकर कार के अंदर ही बिना कार्य की गुणवत्ता देखे बिना ही मूल्यांकन कर रहे है।

अटल यूथ क्रिकेट चेम्पियनशप का हुआ समापन

माही की गूंज, थांदला।

मंडल अध्यक्ष गौलु उपाध्याय के नेतृत्व चल रहे अटल यूथ क्रिकेट चैंपियनशिप में फाइनल मैच बाबुस रतलाम व जीन्स झाबुआ के बीच हुआ, जिसका परिणाम अपनी दमदार गेंदबाजी की बदौलत बाबुस ने आखरी ओवर में जीत दर्ज कर ली। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाभर मौजूद रहे व विजेता टीम बाबुस रतलाम को 51 हजार रूपए व उप विजेता टीम जीन्स झाबुआ को 25 हजार रूपए नकद राशि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक व विशेष अतिथि नपा अध्यक्ष बंटी डामोर द्वारा दि गई, साथ ही ट्राफियां दी गई। आयोजन में भाजपा पेटलावद ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कृष्णपालसिंह गंगाखेड़ी, मेघनगर मंडल अध्यक्ष सचिन प्रजापत, थांदला जनपद उपाध्यक्ष राजेन्द्र भगत खवासा, मंडल महामंत्री कमल चावड़ा, पार्षद पिटर बबेरिया मौजूद रहे। पूरे आयोजन में सरकारी व्यायाम शिक्षकों ने सभी मैचों की अम्पयरिंग की, जिसमे जगत शर्मा, मोहहमद कालीदेवी, विजय जोशी, इमरान, विश्वास शर्मा, राकेश भूरिया, पंकज व्यास, कालूसिंग भूरिया व झाबुआ से सभी व्यायाम शिक्षक जिनकी उपस्थिति से पूरे टूर्नामेंट को बड़ा व भव्य बनाया गया, जिसके लिए मंडल थांदला ने स्व. मीनाक्षी देवि उपाध्याय सेवा समिति की तरफसे प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

कॉम्पलेक्स की जांच के नाम पर गोलमाल, एक माह बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं दे पाया जांच दल

सावन के अंधों को सब तरफ नजर आ रहा हरा-हरा

माही की गूंज, पेटलावद/रायपुरिया

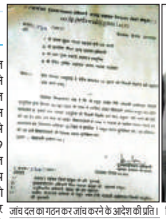

जांच दल का गठन कर जांच करने के आदेश की प्रति।

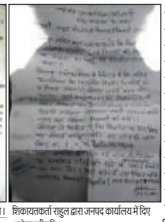

शिकायतकर्ता राहुल द्वारा जनपद कार्यालय में दिए आवेदन की प्रति।

जनपद पंचायत पेटलावद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रायपुरिया के नवीन कॉम्पलेक्स के रिकॉर्ड से संबंधित आवेदक ने 19 फरवरी को जनपद पंचायत कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर कॉम्पलेक्स के रिकॉर्ड के संबंध में जांच की मांग की थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस जांच के विषय को प्राथमिकता से लेते हुए जांच के लिए आदेश जारी किया था जिसके लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सहायक यंत्री दल प्रभारी सावन कुमार घोसले, खंड पंचायत अधिकारी ज्ञानसिंह चौहान, उपयंत्री कलस्टर रायपुरिया पवन गुप्ता और लेखपाल जनपद पंचायत पेटलावद देवेंद्र पुरोहित की टीम गठित की गई थी। इन कर्मचारियों को तीन दिवस में शिकायतकर्ता के समक्ष में नीलामी से संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन कर रिकॉर्ड का जांच करना था और निराकरण प्रतिवेदन 3 दिन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद कार्यालय पेटलावद में प्रस्तुत करना था। 22 फरवरी को उक्त आदेश जारी हुआ और इस आदेश का कर्मचारियों के द्वारा अभी तक नियम अनुसार कोई पालन नहीं किया गया और इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जांच दल न तो रायपुरिया पहुंचा है और न ही शिकायतकर्ता के सामने जांच की गई है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि, यह जांच जनपद पंचायत से होती है या नहीं? वही ग्राम पंचायत सरपंच सुखराम मैडा का कहना है कि, जांच हो गई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता राहुल गोस्वामी से जब चर्चा हुई तो उनका कहना है कि, मुझे प्रतिवेदन की कॉपी नही मिली है और अधिकारी एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए धक्के मार रहे है, अगर 2 दिन में यहां पर जांच नहीं होती है तो मैं कलेक्टर झाबुआ के समक्ष जनसुनवाई में अपनी मांग रखूंगा।

मामले में जांच दल शामिल सभी से बात गई जिस पर लेखपाल पुरोहित का कहना है कि, मैं दल में साथ हुं लेकिन प्रतिवेदन दल प्रभारी को बनाकर देना है और अब तक प्रतिवेदन दिया क्यो नही दिया मुझे नही पता।

वही खंड पंचायत अधिकारी ज्ञानसिंह चौहान ने इस बारे में बताया कि, जांच की गई है प्रतिवेदन अधिकारी तक पहुंचाने का काम दल प्रभारी का है।

वही दल प्रभारी सावन घोसले का कहना है कि, हमने जांच कर ली है और व्यस्तता के कारण जांच प्रतिवेदन दे नही पाया, एक-दो दिन में प्रतिवेदन दे दिया जाएगा।

जांच के नाम पर लेन-देन का खेल, फोन किया तो हरकत में आया जांच दल पहुंचा पंचायत

मिली जानकारी अनुसार जांच के नाम पर आपसी ताल-मेल से जांच को दबाया जा रहा था। गूंज को चर्चा में सभी ने बताया की जांच हो चुकी है, लेकिन गूंज के संज्ञान में मामला आते ही जांच हो चुकी कहने वाला दल मंगलवार को ग्राम पंचायत रायपुरिया पहुंचकर मामले की जांच की। अधिकारी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि, जांच के दौरान शिकायतकर्ता को भी बुलाना था लेकिन शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की सूचना नही दी गई।

आखिर क्या है मामला

शिकायतकर्ता राहुल गोस्वामी का मानना है कि, ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स में निर्माण से लेकर दुकानो के विक्रय तक में भारी अनियमित्ता की गई है, जिसकी जानकारी आरटीआई की माध्यम से ली जा रही है और लिखित शिकायत भी करी है।

नौ माह से बाकी वेतन घर चलना हुआ मुश्किल, लघु वेतन कर्मचारी संघ ने लगाई वेतन भुगतान की गुहार

माही की गूंज, पेटलावद। सोचिये महंगाई के इस दौर में घर चलाना कितना मुश्किल है, ऐसे में मामूली वेतन से अपना घर चलाने वालों को समय पर वेतन नही मिले तो क्या स्थिति बन रही होगी। मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है जहां शिक्षक से लेकर बड़े अधिकारी का वेतन तो महीने की पहली तारीख को जमा हो जाता है, लेकिन इसी विभाग के स्कूल, छात्रावास, आश्रम में कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विगत 9 माह से नही हो पाया है, जिससे इन कर्मचारियों से सामने परिवार के पालन-पोषण की चुनोती खड़ी हो गई है। इन कर्मचारियों द्वारा लगातार वेतन की मांग की जा रही है लेकिन राशि नही होने का हवाला देकर वेतन नही दिया जा रहा है।

मंगलवार को लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी को आवेदन देकर कर्मचारियों के बाकी पड़े 9 माह के वेतन के जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की गई। जिसमे बताया कि, इन कर्मचारियों के सामने अब परिवार के भरण-पोषण तक की चुनोती खड़ी हो गई है और फरवरी माह में जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद भी वेतन भुगतान नही हुआ है।

वहीं जिम्मेदार अधिकारी मामले में फंड नही होने के कारण वेतन का भुगतान नही होने की बात बताकर पल्ला झाड़ रहे है।

बच्चों के हितों की रक्षा हेतु तथा बाल हितैषी पंचायतों के निर्माण में समितियों का क्रियाशील होना जरुरी

ब्लॉक स्तरीय बाल सरंक्षण समिति का पुनर्गठन एवं आमुखीकरण कार्यशाला हुई सम्पन्न

माही की गूंज, बांसवाड़ा/कुशलगढ़। नितिन झाकरेद

बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने एवं बाल मैत्री वातावरण की स्थापना के लिए पंचायत समिति सभागार सज्जनगढ़ मे सेव द चिल्ड्रन, बाल अधिकारिता विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय बाल सरंक्षण समिति का पुनर्गठन एवं आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रधान रामचंद्र डिन्डोर, मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी हेम राज, विकास अधिकारी और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के आथित्य मे सम्पन्न हुआ।

सेव द चिल्ड्रन के दिनेश कुमार ने बताया कि, उक्त आमुखीकरण कार्यशाला का उद्देश्य समेकित बाल सरंक्षण योजना और किशोर न्याय, (बालको की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम 2015 के पालन में उक्त समितियों को प्रभावी संचालन एवं क्रियाशील करने के मध्येनजर किया गया। बाल अधिकार एवं बाल सरंक्षण के मुद्दे तथा ब्लॉक स्तरीय बाल सरंक्षण समिति का उद्देश्य एवं उक्त समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से साझा किया गया।

मुख्य अथिति उपखंड अधिकारी हेमराज ने स्थानीय स्तर पर बच्चो की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, व्याप्त बाल श्रम, बाल विवाह आदि कुरीतियों के रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ढांचो को आगे आकार काम करने को प्रोत्साहित किया। अपने उद्बोधन में बाल सरंक्षण की दिशा में सेव द चिल्ड्रन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और पंचायत के जन प्रतिनिधियों को कहा, हमारे सयुंक्त प्रयासों से ही सज्जनगढ़ ब्लॉक में बच्चो के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जा सकेगा।

कार्यशाला में प्रधान रामचन्द्र डिन्डोर ने अपने वक्तव्य में बताया कि, हमारे क्षेत्र में बच्चो से जुडी हुई अनेको प्रकार की समस्याए हैं जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी तथा बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में इस सदन में उपस्थित सभी ग्राम विकास अधिकारी व सरपंचो की अहम भूमिका हैं कि, वो सभी ग्राम पंचायत स्तर बाल सरंक्षण समिति का गठन सुनिश्चित करे तथा उनकी नियमित बैठके करते हुए इस क्षेत्र के बच्चो को जिस तरीके से अधिनियम की मंशा हैं उसके अनुसार खुशहाल जीवन प्रदान करने हेतु कार्य करे। साथ ही यहाँ पर उपस्थित बाल सरंक्षण समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती हैं कि, प्रत्येक माह बाल सरक्षण समिति की नियमित बैठके का आयोजन करे तथा इन बच्चो से जुड़े हुए मुद्दों का एकजुट होकर कार्य करना शुरू करे।

कार्य शाला में वक्ता विशेषज्ञ एवं सदस्य बाल कल्याण समिति मधुसुदन व्यास द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत कठिन परिस्थितियों एवं जोखिम वाले बच्चो की स्थिति, दुर्दशा आदि का जिक्र किया। कार्यशाला में पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति गोपाल पाण्ड्या ने अपने उद्बोधन में बाल सरंक्षण हेतु सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों और व्यवस्थाओ/सेवाओ के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

कार्यशाला में समस्त ग्राम पंचायतो के सरपंच, सचिव सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी, बीसीएमएचओ, अतिरिक्त विकास अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाल सरंक्षण पुलिस अधिकारी, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी व सेव द चिल्ड्रन के कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे।

बीमार पति के इलाज के लिए सहयोग की मांग, प्रदेश के अस्पतालों में नही काम आ रहा आयुष्मान कार्ड

अधिकारियो ने कहा आयुष्मान कार्ड जिन अस्पताल में चले वहां जाकर इलाज करवा लो

माही कि गूंज, पेटलावद।

पेटलावद की एक महिला मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर पति के इलाज के लिए खर्च होने वाली राशि के सहयोग के लिए आवेदन दिया, लेकिन जनसुनवाई में मौजूद अधिकारीयो ने मामला स्वास्थ्य विभाग को दिया तो, स्वास्थ्य विभाग ने महिला का सहयोग करने के बजाए उन हॉस्पिटल की पर्ची बनाकर दे दी जहां आयुष्मान कार्ड चलता है। पेटलावद की बीपीएल परिवार की गरीब महिला बसंती बाई ने पति की गंभीर बीमारी के ऑपरेशन में आने वाले डेढ़ लाख के खर्च में शासकीय योजनाओं से मदद के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन अधिकारियों ने आयुष्मान योजना का हवाला देकर मामला रफा-दफा कर दिया।

महिला बसंती बाई ने बताया कि, मेरे पति राधकिशन को दिल की बीमारी है जिनका इलाज इंदौर के अस्पताल में चल रहा है और वे अस्पताल के इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट है और वही अपने बीमार पति का इलाज करवा चाहती है, इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड को मान्य नही किया गया जिससे इलाज के लिए लगने वाले बड़े खर्च का मैं गरीब महिला वहन नही कर सकती हूं, प्रशासन के पास सहयोग की अपेक्षा लेकर गई थी लेकिन कोई सहयोग नही मिला।

बाजार से कर्ज लेकर करवाई जांच

पीड़ित परेशान महिला बसंती बाई ने बताया कि, मैंरे व मैंरे पति के पास रोजगार का कोई साधन नही है न ही कोई संतान, जो कुछ था बीमार पति के इलाज में लगा दिया और बाज़ार से कर्ज और परिवार वालो से उधार लेकर सभी जांच व अब तक की दवाइयों का इंतजाम किया है, अब ऑपरेशन के लिए पैसे नही है। बताता दे कि, बसंती बाई का बीपीएल राशनकार्ड भी बना हुआ है जिससे उम्मीद थी कि, बीपीएल परिवार में होने के कारण प्रशासन किसी भी तरह से मदद करेगा जो फिलहाल कहीं होती नजर नही आ रही है।

प्रदेश में ही नही चल रहे आयुष्मान कार्ड, अन्य राज्यो में हालत और खराब

केंद्र की आयुष्मान योजना का वर्त्तमान में भारी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और घर-घर जाकर कार्ड बनाकर टारगेट पूराकर वाह-वाही लूटी जा रही है, लेकिन हकीकत में आयुष्मान योजना का लाभ उतना नही मिल पा रहा जितना उसके प्रचार में बताया जा रहा है। अन्य राज्यो की बात तो दूर प्रदेश के गिने चुने हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड मान्य किए जा रहे है जिससे मरीजों ओर उनके परिजनों की भारी फजियत हो रही है। योजना में जुड़ने से पहले जिन हॉस्पिटलों में मरीज़ों का इलाज चल रहा है परिजन उसी हॉस्पिटल में इलाज लेना चाहते है, लेकिन प्रशासन इस समस्या का हल निकालकर सहयोग करने की बजाए सूची में शामिल हॉस्पिटल का पता बताकर इतिश्री कर लेते है। योजना के कार्ड की स्थिति अन्य राज्यो में तो और भी गम्भीर है, जहां आयुष्मान कार्ड को लेकर परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और अंत मे निजी खर्च से ही ईलाज करवाना पड़ रहा है। प्रशासन के पास ये आंकड़ा बताने का समय तो है कि, अब तक योजना के कितने कार्ड बनाए गए है लेकिन कितने लोगो को इसका लाभ मिल रहा है इससे कोई लेना-देना नही है।

कई योजनाएं है जिनसे मिल सकता था सहयोग

पीड़ित महिला का परिवार बीपीएल में आता है और सरकार की आयुष्मान योजना के अलावा भी कई प्रकार की योजनाएं संचालित है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर सहयोग किया जा सकता था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने उनमें कोई रुचि नही दिखाई। जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसे कई फंद होते है जिससे परिवार की मदद की जा सकती थी।

सांसद विधायक से भी की मांग, सांसद प्रतिनिधि ने कहा सांसद निधि बन्द है, विधायक प्रतिनिधि ने कहा पूरी कोशिश करूंगा

महिला ने अपने पति के इलाज के लिए राशि जुटाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए और इसके लिए सांसद एवं विधायक को भी आवेदन देने की तैयारी की, लेकिन सांसद के दिल्ली और विधायक के भोपाल में होने के कारण आवेदन नही दे पाई। इस संबंध में उनके प्रतिनिधियो से सहयोग की मांग की, जिस पर सांसद प्रतिनिधि राजेश कासवा से बात की तो उनका कहना है कि, सांसद निधि बन्द हो चुकी है ऐसे में इतनी राशि का सहयोग कर पाना सम्भव नही है, लेकिन सांसद महोदय के आते ही महिला और उसके पति को दस-दस हजार की आर्थिक सहायता करवाने का पूरा प्रयास करूंगा।

वही विधायक प्रतिनिधि आशीष मुथा ने कहा है कि,

- इंदौर में आगा इलाज करवा रहे राधकिशन।

महिला के आवेदन के साथ बीमारी के सारे दस्तावेज मेरे पास आ गए है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि, विधायक निधि से अधिक से अधिक राशि स्वीकृत करवाकर परिवार का सहयोग कर सकूं।

जनप्रतिनिधियों पर खड़े हो रहे सवाल

सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़े हो रहे है जो कुर्ता-पजमा पहनकर सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाते है लेकिन पीड़ित और परेशान लोग इनको नही दिखते, अगर दिख भी जाते है तो सरकार में होने के बाद भी प्रशासन पर दबाव बनाकर सहयोग नही करवा पाते और चुनाव के समय सरकारी योजनाओं को ही लेकर आम जनता के बीच जाते है। फिलहाल सांसद और विधायक दोनों के प्रतिनिधियों ने सहयोग की बात तो की है लेकिन अब ये देखना होगा कि, महिला को बीमार पति के इलाज के लिए समय पर सहयोग कर पाते है या नही।

संपादकीय

केंद्र के नए नियम स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रित करने का है प्रयास

हालिया समय में भारत ने प्रमुख संस्थानों में गंभीर गिरावट देखी गई है, जिसने इसके संवैधानिक लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। भारतीय नागरिक संसद और न्यायपालिका के कामकाज में आई गिरावट को लेकर चिंता जता ही चुके हैं, अब रही-बची कसर पूरी करने के लिए मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसी गिनती में आ गया है। सरकार द्वारा पिछले दिनों लाए गए नए आईटी नियम कार्यपालिका को अभूतपूर्व शक्तियां देते हैं, जहां अस्पष्ट आधार पर बिना प्रकाशक को उनकी बात कहने का मौका दिए, डिजिटल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म का कंटेट हटाया जा सकता है और यह इंटरनेट आधारित सभी मीडिया मंचों जिनमें समाचार, मनोरंजन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे ओटीटी ऐप और फेसबुक, ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया मंच शामिल हैं, को विनियमित करने के नाम पर हो रहा है। सरकार ने डिजिटल न्यूज़ सामग्री को नियंत्रित करने के लिए अनुचित तरीके से बिना किसी संसदीय चर्चा के इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून, जो ऑनलाइन मंचों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, का विस्तार किया है। यह साफतौर पर संसद का अपमान है। इससे भी खराब यह है कि, नए नियम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को बिना प्रकाशक से चर्चा किए डिजिटल न्यूज़ सामग्री को सेंसर करने की आपात शक्ति प्रदान करते हैं।

संक्षेप में कहें, तो इन शक्तियों के साथ नौकरशाह सबसे बड़े संपादक और सेंसर हो जाएंगे! इस कदम से पूरी मीडिया बिरादरी हैरान है, जिसे अब तक यही लगा था कि, नए दिशा-निर्देश मुख्य तौर पर सोशल मीडिया मंचों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए होंगे, जो बीते कुछ समय से सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं। यहां तक कि, ये सभी भी नई त्रिस्तरीय नियामक प्रणाली को लेकर चिंतित हैं, जहां अंतरविभागीय कमेटी इन पर करीब से नजर रखेगी, जिसके प्रमुख सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों से आने वाले नौकरशाह होंगे। संबंधित मंच इसे सरकार द्वारा सेल्फ-रेगुलेशन को नियमों के दायरे में बांधने का तरीका कह रहे हैं। जहां इन सभी मंचों के विनियमन पर विचार किया जा रहा था, वहीं ऑनलाइन न्यूज़ मंचों ने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि, उन्हें इसके समान नियमों से जोड़ा जाएगा।

कानूनविदों का मानना है कि, आईटी अधिनियम के तहत आने से चीजों के साथ ऑनलाइन समाचार सामग्री को रखना इस अधिनियम के आगे की बात है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मिली बोलने की आजादी का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, मीडिया की आज़ादी से जुड़ा इस तरह का कोई बदलाव संसद या इससे संबंधित लोगों से बिना कोई किए चर्चा किए लाया गया है। केवल संसद ही अभिव्यक्ति संबंधी विनियमन का कानून ला सकती है और यह संविधान की मूल संरचना के अनुकूल होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने न्यूज़ मीडिया संथाओं के लिए गलत श्रेणियां बनाई हैं। मिसाल के तौर पर प्रिंट अख़बारों को इन नए कड़े नियमों के दायरे में नहीं लाया गया है, जबकि इनके डिजिटल कंटेंट पर ये नियम लागू होंगे जबकि इसकी अधिकतर सामग्री समान है। यानी कि अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी लेख को हटाते हैं, तो वह अख़बार में तो बना ही रहेगा। नए दिशानिर्देश इस तरह के विरोधाभासों से भरे हुए हैं। आने वाले समय में अखबारों के पारंपरिक पाठक और राजस्व डिजिटल स्वरूप से ही आएंगे, ऐसे में प्रिंट मीडिया को नए नियमों से बाहर रखने का कोई अर्थ नहीं है।

प्रकाशकों को सुने बिना किसी समाचार सामग्री को हटाए जाने की आपात शक्तियों से सभी मीडिया संस्थान प्रभावित होंगे, किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में कार्यपालिका के पास न्यूज़ मीडिया सामग्री को विनियमित करने की इतनी शक्ति नहीं है। सबसे अच्छा, वे स्व-नियमन का पालन करते हैं, जहां कार्यपालिका एक उचित दूरी पर है। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि, भारत की लोकतांत्रिक साख और न गिरे, तो उन्हें सरकार के इस फैसले को वापस लेना होगा।

धर्म निरपेक्षता के पाखंड का टूटता मिथक

जय श्रीराम के नारे पर आपत्ति जताने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धर्म निरपेक्षता के पाखंड का मिथक इस चुनाव में टूटता दिख रहा है। चोला बदलते हुए अब ममता नंदीग्राम में शिव मंदिर पर जलाभिषेक करती दिखीं, वहीं स्वयं को देवी चंडी की भक्त और ब्राह्मण भी कहकर प्रचारित कर रही हैं। हिंदू मतदाताओं को साधने की दृष्टि से यह उनका मुस्लिम तुष्टिकरण से बाहर आने का स्वांग है। जबकि मार्क्सवादियों से सत्ता छीनने से लेकर दस साल मुख्यमंत्री बने रहने के दौरान न केवल उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि रामनवमी और दुर्गा पूजा के उत्सवों में भी व्यवधान डालती रही हैं। इसके उलट उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए न केवल हिजाब ओढ़ा, बल्कि उन्हीं की तर्ज पर इबादत भी की। कई बार तो हिंदुओं को अदालत के हस्तक्षेप के बाद सार्वजनिक स्थलों पर दुर्गा पूजा की अनुमति मिली। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में वोटबैंक बनाने की दृष्टि से इनकी नागरिकता के लिए आधार कार्ड जैसे पहचान-पत्र बनाए गए।

ममता के इस पाखंड और नंदीग्राम में हुए हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने करारा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि, ममता अब स्वयं को देवी चंडी की भक्त और ब्राह्मण बता रही हैं, जबकि आज के पहले उन्होंने अपनी धार्मिक निष्ठा और जातीयता का खुलासा कभी नहीं किया। ममता पर हमला भी एक नौटंकी है। क्योंकि मुख्यमंत्री के काफिले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल चलता है। हैरानी की बात यह है कि, चार-पांच युवकों ने उन पर हमला किया, बावजूद न तो पुलिस ने उन्हें पकड़ा और न ही यह हमला वीडियो फुटेज के रूप में सामने आया। लिहाजा यह सब प्रपंच सहानुभूति बटोरने की कोशिश भर है। अब तो मीडिया भी इस हमले को फेक बता रहा है।

हिंदुत्व के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं पक्षों का चुनाव में इस्तेमाल कर केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाईं। मुस्लिम तुष्टिकरण किए बिना और वोट मिले बिना भाजपा का दूसरी बार केंद्रीय सत्ता में आना इस बात का प्रतीक है कि, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया जाए, तो सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। इसलिए धर्म निरपेक्षता के जितने भी पैरोकार हुए हैं, वे अब अपने छद्म आचरण से मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कमलनाथ ने भगवान राम के वनवास के दौरान पथगमन को विकसित करने की योजना बनाकर धर्म निरपेक्षता के मिथक को तोड़ा था। इसी से अब कदमताल मिलाती ममता दिख रही हैं। ममता को हिंदू घोषित करने की जरूरत व मजबूरी इसलिए भी आन पड़ी है, क्योंकि बंगाल भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जनसभाएं कर हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को उभार दिया है। इसी वजह से एक-एक कर तृणमूल और कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल होकर ममता के वर्चस्व के लिए चुनौती बन गए हैं।

पश्चिम बंगाल में हिंसा चरम पर है, दूसरी ओर एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद, विधायक व अन्य कार्यकर्ता भाजपा के पाले में समाते जा रहे हैं। कभी वामपंथियों की मांद में घुसकर दहाड़ने वाली ममता अपने ही घर में अकेली पड़ती दिख रही हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह एक-एक करके तृणमूल के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे लगता है ममता घोर राजनीतिक संकट से घिरती जा रही हैं। ममता ने वामपंथियों के जबड़े से जब सत्ता छीनी थी, तब उम्मीद बनी थी कि, वे अनूठा नेतृत्व देकर बंगाल में विकास और रोजगार को बढ़ावा देंगी। लेकिन दस साल के शासन में अविवाहित होने के बावजूद वे वंशवाद, मुस्लिम तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और हिंसा से बंगाल को मुक्ति नहीं दिला पाईं, बल्कि इन विकृतियों की पैरोकार बन गईं।

यही कारण रहा कि, अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति के चलते आज तृणमूल और ममता का भविष्य अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। ममता को सबसे बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी के अलग होने से लगा है। इसके बाद ममता की देहरी फ्लांगने का सिलसिला चल पड़ा है। इसकी एक वजह ममता का तानाशाही आचरण तो है ही, राजनीति में तकनीक के जरिए जीत के खिलाड़ी माने जाने वाले प्रशांत किशोर का पार्टी में बढ़ता दखल भी है।

हाल के दिनों में तृणमूल को जिन दिग्गज नेताओं ने छोड़ा है, उनमें सबसे ताकतवर शुभेंदु अधिकारी हैं। ममता ने जिस नंदीग्राम से खुद चुनाव लड़ने की ठानी हैं, वहीं से भाजपा प्रत्याशी के रूप में शुभेंदु पचास हजार से भी अधिक मतों से ममता बनर्जी को हराने का दावा अभी से करने लगे हैं। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी भी विधायक और सांसद रह चुके हैं। शुभेंदु के एक भाई सांसद और दूसरे नगरपालिका अध्यक्ष हैं। इस तरह इनके परिवार का छह जिलों की 80 से ज्यादा सीटों पर असर है। सर्वहारा और किसान की पैरवी करने वाले वाममोर्चा ने जब सिंगूर और नंदीग्राम के किसानों की खेती की जमीनें टाटा को दीं तो इस जमीन पर अपने हक के लिए उठ खड़े हुए किसानों के साथ ममता आ खड़ी हुई थीं।

ममता कांग्रेस की पाठशाला में पढ़ी थीं। जब कांग्रेस उनके कड़े तेवर झेलने और संघर्ष में साथ देने से बचती दिखी तो उन्होंने कांग्रेस से पल्ला झाड़ा और तृणमूल कांग्रेस को अस्तित्व में लाकर वामदलों से भिड़ गईं। इस दौरान उनपर कई जानलेवा हमले हुए, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। जबकि 2001 से लेकर 2010 तक 256 लोग सियासी हिंसा में मारे जा चुके थे। यह काल ममता के रचनात्मक संघर्ष का चरम था, जिसके मुख्य रचनाकार शुभेंदु अधिकारी ही थे। इसके बाद 2011 में बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए। ममता ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर वाममोर्चा का लाल झंडा उतारकर तृणमूल की विजय पताका फहरा दी थी।

प्रमोद भार्गव

अब बंगाल की माटी पर एकाएक उदय हुई भाजपा ने ममता के वजूद को संकट में डाल दिया है। बंगाल में करीब 27 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें 90 फीसदी तृणमूल के खाते में जाते हैं। इसे तृणमूल का पुख्ता वोट बैंक मानते हुए ममता ने अपनी ताकत मोदी व भाजपा विरोधी छवि स्थापित करने में खर्च दी। इसमें मुस्लिमों को भाजपा का डर दिखाने का संदेश भी छिपा था। किंतु इस क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हिंदुओं में स्वस्फूर्त ध्रुवीकरण के रूप में दिखाई देने लगी। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए एनआरसी लागू होने के बाद भाजपा को वजूद के लिए खतरा मानकर चल रहे हैं, नतीजतन बंगाल के चुनाव में हिंसा का उबाल आया हुआ है। इस कारण बंगाल में जो हिंदी भाषी समाज है वह भी भाजपा की तरफ झुका दिखाई दे रहा है।

हैरानी इस बात की है कि, जिस ममता ने परिवर्तन का नारा देकर वामपंथियों के कुशासन और अराजकता को चुनौती दी थी, वही ममता इसी ढंग की भाजपा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बौखला गई है। उनके बौखलाने का एक कारण यह भी है कि, 2011-2016 में उनके सत्ता परिवर्तन के नारे के साथ जो वामपंथी और कांग्रेसी कार्यकर्ता आ खड़े हुए थे, वे भविष्य की राजनीतिक दिशा भांपकर भाजपा का रुख कर रहे हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में जब बंगाल में हिंसा का नंगा नाच हो रहा था, तब ममता ने अपने कार्यकताओं को विवेक न खोने की सलाह देते हुए नारा दिया था, 'बदला नहीं, बदलाव चाहिए।' लेकिन बदलाव के ऐसे ही कथन अब ममता को असामाजिक व अराजक लग रहे हैं।

भारत क्यों बने किसी का मोहरा?

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया। इन चार राष्ट्रों के चौगुटे का जो पहला शिखर-सम्मेलन हुआ, उसमें ध्यान देने वाली बात यह हुई कि, किसी भी नेता ने चीन के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला जबकि माना जा रहा है कि, यह चौगुटा बना ही है, चीन को टक्कर देने के लिए। इसका नाम है क्वाड याने ''क्वाड्रीलेटरल सिक्यूरिटी डॉयलाग'' अर्थात सामरिक समीकरण ही इसका लक्ष्य है लेकिन इसमें भाग ले रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मोरिसन ने अपना ध्यान केंद्रित किया, कोरोना महामारी से लड़ने पर। पिछले माह जब इसके विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, तब भी चाहे अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के विरुद्ध जब-तब कुछ बयान दिए थे लेकिन चारों विदेश मंत्रियों का कोई संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं हो सका, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि, यह चौगुटा चीन-विरोधी मोर्चा बन जाए। भारत आज तक किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। शीत-युद्ध के दौरान वह सोवियत संघ के नजदीक जरुर रहा लेकिन वह किसी सेन्टो या नाटो के सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। चीन ने इस चौगुटे को पहले ही 'एशियाई नाटो' घोषित किया हुआ है। इसमें शक नहीं है कि, पिछले 10-15 साल में चीन की

चुनौती से अमेरिका प्रकपित है और इसीलिए उसने प्रशांत-क्षेत्र को भारत-प्रशांत क्षेत्र (इंडो-पेसिफिक) घोषित किया, लेकिन भारत के नेता इतने कच्चे नहीं हैं कि वे अमेरिकी गोली को निगल जाएंगे। वे अमेरिका की खातिर चीन से दुश्मनी नहीं बांधेंगे। खुद बाइडन का अमेरिका चीन के साथ टक्कर जरुर ले रहा है लेकिन वह ट्रंप की तरह बेलगाम नहीं है। इसके अलावा उसे पता है कि, जापान और आस्ट्रेलिया का चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अमेरिका के यूरोपीय साथी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं का चीन एक बड़ा सहारा है। इसीलिए इस शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य में चारों देशों ने कहा है कि, यह चौगुटा समान विचार वाले देशों का लचीला संगठन है इसमें कुछ नए देश भी जुड़ सकते हैं। यह ठीक है कि, प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने अपने-अपने सामरिक अड्डे बना रखे हैं और चीन व उनके हितों में सामरिक प्रतिस्पर्धा भी है लेकिन भारत किसी भी राष्ट्र या गुट का मोहरा क्यों बनेगा? भारत और चीन के बीच सीमांत को लेकर आज-कल तनाव जरुर बना हुआ है लेकिन उस पर वार्ता चल रही है। इसके अलावा भारत और चीन 'ब्रिक्स' और 'एससीओ', इन दो संगठनों के सहभागी सदस्य भी हैं। चीन से आपस में निपटने में भारत सक्षम है। इसलिए भारत इस चौगुटे का फायदा उठाते हुए भी किसी का मोहरा क्यों बनेगा?

महंगाई की रफ्तार

सिद्धार्थ शंकर

खाने-पीने के सामान, ईंधन और बिजली के दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई फरवरी में लगातार दूसरे महीने बढ़कर पिछले 27 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर फरवरी में 4.17 फीसदी रही जो इस साल जनवरी में 2.03 फीसदी और पिछले साल फरवरी में 2.26 फीसदी थी। पिछले हफ्ते आए आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर फरवरी में 5.03 फीसदी रही थी। खाने-पीने के सामान के थोक दाम में महंगाई पिछले महीने 3.31 फीसदी रही। साल के पहले महीने में उनका थोक दाम सालाना आधार पर 0.26 फीसदी घटा था। फरवरी में सब्जियों के दाम में 2.90 फीसदी की गिरावट आई जबकि जनवरी में उनके दाम सालाना आधार पर 20.82 फीसदी घटे थे। हालांकि, फरवरी में दलहन का दाम 10.25 फीसदी बढ़ गया जबकि फलों के दाम में 9.48 फीसदी का इजाफा हुआ। पिछले एक साल से लोगों को जिस तरह के गंभीर संकट से गुजरना पड़ रहा है, खासतौर पर आर्थिक मुश्किलों से, उसमें अब और महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। करोड़ों परिवारों के पास काम-धंधा नहीं है और दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई की मार से त्रस्त मध्य वर्ग और निम्न वर्ग का बड़ा हिस्सा बिना सबसिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल करता है। डीजल महंगा होने का पहला असर माल ढुलाई पर पड़ता है और इससे रोजमर्रा की जरूरतों का हर सामान महंगा होता जाता है। सामान्य स्थितियों में जरूरी चीजों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का आम लोगों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आय के साधनों की अनिश्चिता छाई हो तो ऐसे में जरूरी उपभोग की चीजों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी नया तनाव दे जाती है। पिछले कुछ समय से पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से यह चिंता गहरी होती जा रही है कि, अगर महंगाई इसी तरह बेलगाम रही तो कुछ समय बाद आम लोगों के सामने गुजारा करने के कितने विकल्प बचेंगे! पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तय करने की नीति भले कुछ भी हो, लेकिन वह इतनी तर्कसंगत तो होनी ही चाहिए कि, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित न हो। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम सामान्य स्तर पर बने रहने के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सरकारें अपना खजाना भर रही हैं।

कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार यह कहा कि, केंद्र और राज्यों को मिलकर पेट्रोलियम उत्पादों पर लग रहे करों में कटौती करने के बारे में सोचना चाहिए। सच्चाई यह है कि, सरकारें लोगों की मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रही हैं। खाना-पीना कोई बंद नहीं करने वाला, यात्रा लोग करेंगे ही, जरूरत का सामान खरीदेंगे ही, ऐसे में करों की आड़ में आमजन की जेब से जितना पैसा पैसा खींचा जा सकता है, खींच लें। यह बेरहमी की पराकाष्ठा है। क्या ऐसी सरकारें ही कल्याणकारी होती हैं? पिछले करीब साल भर से महामारी की मार के चलते बाजार से लेकर रोजगार के तमाम क्षेत्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। हालत यह है कि, लोगों की आमदनी तो घट या फिर ठहर गई है, लेकिन अमूमन हर वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी के साथ उनके खर्चे भी बढ़ गए हैं। महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाई गई पूर्णबंदी के दौरान करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी छिन गई और सब कुछ बंद रहने की वजह से आय का भी कोई जरिया नहीं रहा था। उसके बाद क्रमशः ढिलाई के साथ हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। कहा तो यह है कि, भारत में साधारण परिवारों में छोटे स्तर पर की जाने वाली घरेलू बचतों की प्रवृत्ति के चलते लोग कुछ समय तक अभाव का सामना कर लेते हैं। लेकिन अगर इस स्थिति में निरंतरता बनी रहे तो बहुत दिनों तक लोग खुद को नहीं संभाल सकते। सरकार को जहां महंगाई में कमी लाने के लिए तत्काल ठोस पहल करनी चाहिए, वहीं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के जरिए लोगों की क्रयशक्ति में इजाफा करने का भी इंतजाम करना चाहिए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि, महंगाई का सबसे मारक असर उसी निम्न, मध्यम और कमजोर तबकों पर पड़ता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।

निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण! राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है

हरियाणा में राज्य सरकार ने हाल ही में एक नए कानून को अधिसूचित किया है, जिसके मुताबिक, राज्य में निजी क्षेत्र की 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। भारत में उप-राष्ट्रवाद कोई नई चीज नहीं है। विशुद्ध राजनीतिक नजरिए से शायद यह एक ऐसे देश में हैरान करने वाली बात भी नहीं है, जहां बहुत सारे लोग बहुत कम उपलब्ध नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इस संदर्भ में हरियाणा कुछ नया नहीं कर रहा है। बढ़ती बेरोजगारी और लोगों के असंतोष से जूझते हुए कई राज्यों ने (महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश) हाल के दिनों में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने की कोशिश की है। हरियाणा बस ऐसे कई राज्यों में से नया उदाहरण है, जो निजी क्षेत्र की नौकरी में आरक्षण को लागू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि, इतिहास हमें बताता है, एक सार्वजनिक नीति के रूप में यह नुकसानदेह है। बढ़ती बेरोजगारी का सामना करते हुए आंध्र प्रदेश ने भी ऐसे ही कानून को पारित करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे असांविधानिक बताकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। फिर कर्नाटक ने भी हाल ही में इसी तरह के प्रावधानों के जरिए वर्ष 2020 में निजी क्षेत्र को स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता देने के लिए कहा था। लेकिन राज्य के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि, कंपनियां उसके निर्देशों का अनुपालन कर रही हैं या नहीं।

दरअसल भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद जन्म स्थान के आधार पर रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाते हैं। जैसा कि, जनवरी 2017 में प्रवासन पर कार्य समूह की रिपोर्ट में बताया गया, 2014 में चारू खुराना बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट रूप से कहता है कि, रोजगार के मामले में आवास के आधार पर प्रतिबंध असांविधानिक है। दूसरी बात, इतनी ही सख्त आलोचना इसके शुद्ध कार्यान्वयन को लेकर है। इस तरह का कानून अनिवार्य रूप से कानूनी बाधाओं में चलता है। अब आंध्र प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए, निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण लागू करने वाला यह पहला राज्य बना। हालांकि इस विधेयक को असांविधानिक बताकर राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इसके खिलाफतर्क दिया जाता है कि, यह संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस कानून को राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, इसलिए इस कानून को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश ने भी स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरी में 70 फीसदी आरक्षण कोटा लाने का वादा किया है। लेकिन कई वकीलों का कहना है कि, मध्य प्रदेश के कानून की भी वही नियति होगी, जो आंध्र प्रदेश में निजी नौकरी में आरक्षण कोटे की हुई है। ऐसे में भारत की राज्य सरकारों को, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों, समझना चाहिए कि, अंतरराज्यीय प्रवासन में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। यह किसी भी अन्य देश के विकास की दिशा-दशा से स्पष्ट है। स्थानीयतावादी कानूनों में वृद्धि से देश में दरारें गहरा रही हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जो कई अंतर-राज्य प्रवासियों का स्रोत है, अन्य राज्यों के उन कानूनों से प्रभावित होगा, जो निजी क्षेत्र के काम को केवल स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत कम कामगारों के पास सुरक्षित नौकरी है। कामगारों का विशाल बहुमत अनिवार्य रूप से निजी क्षेत्र का हिस्सा है और ऐसे कानूनों से वे श्रमिक बुरी तरह प्रभावित होंगे, जो गरीब हैं। हरियाणा के कानून में आय की सीमा (कटऑफ) से यह स्पष्ट हो जाता है कि, अमीर और कुशल श्रमिक काम करने के लिए भारत में कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि, इसी तरह के अवसर अंतर-राज्यीय गरीब प्रवासी श्रमिकों को देने से इन्कार किया जाता है। यह समानता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। जैसा कि प्रवासन विद्वान तुम्बे कहते हैं, 'इस कानून के साथ मूलभूत समस्या यह है कि, कम आय वाले प्रवासी श्रमिक एक बार फिर भारत की सार्वजनिक नीतियों के शिकार बन जाएंगे।'

लेखक - अशोक भाटिया

यह शुभ संकेत नहीं कि, झारखंड सरकार भी निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। भले ही निजी क्षेत्र की नौकरियां स्थानीय लोगों को देने वाले फैसलों के जरिए जनता को यह संदेश देने की कोशिश की जाती हो कि, सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ऐसे कदम कुल मिलाकर निजी क्षेत्र को हतोत्साहित ही करते हैं। इससे भी खराब बात यह होती है कि, वे पिछले दरवाजे से इंस्पेक्टर राज की वापसी का कारण भी बनते हैं। इसके नतीजे में नए उद्योग-धंधे स्थापित करने वाले भी हतोत्साहित होते हैं और वे किसी अन्य राज्य में संभावनाएं तलाशते हैं। ऐसे कदम क्षेत्रीयता की भावना को हवा देकर जाने-अनजाने राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का भी काम करते हैं। आज जब एक देश-एक राशन कार्ड ,एक मोबाइल नंबर ,एक बैंक खाता नंबर जैसे विचारों को अमल में लाने की पहल की जा रही है, तब यह ठीक नहीं कि कुछ राज्य देश की जनता के बीच नई दीवारें खड़ी करने का काम करें।

एक सलाह

दुनिया में सिर्फ दिल ही है, जो बिना आराम किये काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो चाहे वो अपना हो या अपने का।

काम की बात

मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नही होती, उसके लिए एक अछे मन की जरूरत होती है।

प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, अतिक्रमणकर्ता विक्रेताओं ने सब्जी फेंककर जताया आक्रोश

माही की गूंज, मंदसौर।

नगर पालिका और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम नेहरू बस स्टैंड पर पहुंची, यहां पर फूल विक्रेताओं द्वारा दुकान के आगे किए गए अतिक्रमण एवं भांग दुकान से सरोवर भोजनालय वाले रास्ते पर डिवाइडर के आस-पास हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। सब्जी विक्रेताओं के अतिक्रमण हटाने पर विक्रेता नाराज हो गए और विक्रेताओं ने सब्जी फेंककर आक्रोश जताया। इस दौरान अमले ने अतिक्रमण कर रखे गए सामान को जब्त कर वाहन में भरा गया व करीब एक घंटे से अधिक समय तक यहां कार्रवाई चलती रही। अतिक्रमण हटाने के दौरान सब्जी विक्रेता महिलाओं एवं अन्य दुकानदारों ने जमकर विरोध किया, लेकिन अधिकारियों के सामने एक नहीं चली और अमले ने सभी का अतिक्रमण हटा दिया। सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटने के बाद नेहरू बस स्टैंड के पीछे वाला मार्ग चौड़ा दिखने लगा है।

नगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि, बस स्टैंड क्षेत्र में सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने वाले मार्ग पर

सब्जी के ठेलों के कारण बसों के आवागमन में परेशानियां उत्पन्न हो रही थीं, बस चालक व बस संचालक भी सड़क पर लगे हाथ ठेलों को हटाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद मंगलवार को नपा और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस ने एक दिन पहले अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी थी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में यहां सामान जब्त किया गया।

सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि, हम वर्षों से यहां पर अपने ठेले लगा रहे हैं, प्रशासन की टीम ने आकर हमें हटा दिया, अब हम कहां जाएंगे। कार्रवाई के दौरान अमले ने कई दुकानदारों का सामान जब्त किया और सामान उठाकर भी फेंका। रोडवेज बस स्टैंड पान विक्रेता का सामान भी फेंका गया। समीप चाय की दुकान के बाहर लगी भट्ठी को भी नीचे गिराकर अमला जब्त कर ले गया।

यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि, बस स्टैंड क्षेत्र में दुकानदारों व सब्जी विक्रेताओं ने अतिक्रमण कर लिया था। नपा के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। सब्जी विक्रेताओं ने ही अपनी सब्जी फेंकी है। हमारे द्वारा सिर्फ सामान जब्त किया गया है।

राजस्व निरीक्षक नपा राजेश दावरे ने बताया कि, बस स्टैंड के पीछे वाली रोड पर अतिक्रमण होने से बसों के आवागमन में दिक्कत हो रही थी। बस संचालक और चालकों द्वारा भी शिकायत की जा रही थी। मंगलवार को मार्ग पर सभी अतिक्रमण को हटाकर मार्ग को चौड़ा किया गया है। अब यहां पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए लगातार नजर रखी जाएगी।

आरपीएफटीम ने ई टिकट बनाने वाले दो दलालों को किया गिरफ्तार

माही की गूंज, भानपुरा (मंदसौर)

भानपुरा थाना क्षेत्र के गांव बाबुल्दा में सोमवार को आरपीएफथाना शामगढ़ की टीम ने ई-टिकट का गोरखधंधा करने वाले दो दलालों को गिरफ्तार किया। आरोपी फिनो पेमेंट बैंक का संचालन करते हैं और इसी की आड़ में ई-टिकट बरामद हुआ है। आरपीएफने दोनों आरोपियों को रेल्वे की धारा 143 के तहत मंलवार को रतलाम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। आरपीएफथाना प्रभारी प्रताप सिंह, उप निरीक्षक कृष्णपाल शर्मा, हेड कांस्टेबल प्रह्लाद सिंह के नेतृत्व में ई-टिकट बनाने वाले दलाल को दबोचा है, जो शाहदाब हुसैन पिता उमरदराज रंगरेज (31) निवासी मकान नंबर 151 वार्ड नंबर 2 बस स्टैण्ड बाबुल्दा और दूसरा मनीष पिता भेरूलाल राठौर निवासी बाबुल्दा है। उनके पास से कुल तीन पर्सनल यूजर आईडियों से कुल 82 ई-टिकट बनाकर ग्राहकों को उपलब्ध कराना बताया है। उनके पास से सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर, लैपटॉप, माउंस बरामद किए हैं।

वेयर हाउस में रखा चना और मसूर एसडीएम के आदेश से ही निकलेगा

माही की गूंज, मंदसौर।

22 मार्च से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने से पहले एक अहम व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सरकारी व निजी वेयर हाउस में रखे चना व मसूर की निकासी प्रतिबंधित कर दी है, इसे संबंधित एसडीएम की अनुमति लेने के बाद ही निकला जा सकेगा।

समर्थन मूल्य पर सालों से खरीदी हो रही है लेकिन इस तरह की पाबंदी पहली बार लगी है। अधिकारी बताते हैं कि, यह पाबंदी इसलिए लागू की जा रही है जिससे कि वेयर हाउस में रखे चना या मसूर को निकालकर दोबारा खरीदी केंद्रों पर न ले जाया जाए। हैरानी की बात यह है कि, अब अचानक सरकार को यह समझ में आया है कि इस तरह एक ही उपज को बार-बार बेचा जा सकता है।

एसडीएम बिझरीसिंह ने भी बताया कि, खरीदी में किसी भी तरह की डुप्लीकेसी यानी पुनरावृत्ति की आशंका को रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था लागू की है।

इस तरह की है आशंका

जानकार बताते हैं कि, अगर अधिकारियों के साथ मिलीभगत हो तो सब संभव है। इसके अलावा वेयर हाउस के मालिकों में ज्यादातर के पास जमीन भी रहती है, कागजों पर वे खुद को किसान साबित कर सकते हैं। ऐसे में वेयर हाउस में रखी पुरानी फसल को वे दोबारा से बेच सकते हैं।

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: डिप्टी रेंजर को रिश्वत लेते धराया

एक के बाद एक रिश्वत लेते धराए जा रहे है अधिकारी

माही की गूंज, रतलाम।

लोकायुक्त पुलिस के दल ने वन विभाग के डिप्टी रेंजर को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे वन विभाग के सागोद रोड स्थित कार्यालय पर ही कार्रवाई की गई। लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि, शेरानीपुरा रतलाम निवासी सुलेमान खान ने 13 मार्च को लोकायुक्त उज्जैन कार्यालय को आवेदन देकर बताया कि, रतलाम के डिप्टी रेंजर तनवीर खान द्वारा 1 मार्च को लकड़ी से भरा उनका वाहन पकड़ा था जो बाद में 20 हजार रुपए का जुर्माना कर छोड़ दिया, लेकिन जुमाने के नाम पर 70 हजार रुपए अलग से वसूल लिए। इसके बाद भी 50 हजार रुपए की मांग की जा रही थी।

आवेदक सुलेमान द्वारा वन विभाग में लकड़ी परिवहन के लिए आवेदन करने के बाद टीपी (परिवहन अनुमति) जारी करने व भविष्य में गाड़ी नहीं पकड़ने को लेकर डिप्टी रेंजर तनवीर खान ने 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। लोकायुक्त दल ने रिश्वत मांगने की रिकार्डिंग भी करवाई। इसके बाद लोकायुक्त एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में ट्रेप दल गठित किया गया।

मंगलवार दोपहर लोकायुक्त निरीक्षक वर्मा व टीम आरक्षक संजय पटेल, सुनील परसाई, नीरज राठौर, विशाल रेशमिय, उमेश विभाग के कार्यालय पहुंचे और घेराबंदी की। आवेदक सुलेमान खान से वन मंडल कार्यालय में 25 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते ही दल ने डिप्टी रेंजर को मौके पर ही पकड़ लिया। आरोपित तनवीर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। निरीक्षक वर्मा ने बताया कि, आरोपित की संपत्ति का आंकलन भी किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति होने पर कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले भी रतलाम जिले से रिश्वतखोरी का मामला सामने आ चूका है। बता दें कि, 12 मार्च को रतलाम जिले में जावरा नगर पालिका सीएमओ नीता जैन और राजस्व निरीक्षक विजय शक्तावत को दफ्तर में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, रतलाम जिले में लोकायुक्त पुलिस की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है।

स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ महाराज पर हुए प्राण घातक हमले व लूट के विरोध में रहा बंद

माही की गूंज, मंदसौर।

देश की प्रमुख चार शंकराचार्य मठों के बाद भानपुरा पीठ, पांचवी पीठ के रूप में विगत लगभग 300 वर्षों से देश-विदेश में ख्यात व स्थापित है। श्री भानपुरा शंकराचार्य मठ से स्वामी दिव्यानंदजी तीर्थ महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य व वर्तमान पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री ज्ञानानंदजी तीर्थ महाराज पर विगत 11 मार्च को लखनऊ के चकगजा गिरी आश्रम कमलाबाद बड़ौली में बाबा विश्वनाथ गिरी आश्रम में हुए हमले एवं लूट की घटना हुई है। जिससे स्वामी श्री एवं भानपुरा शंकराचार्य मठ की पीठ पर आघाद विश्वास एवं श्रद्धा रखने वाले भानपुरा नगर ही नहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं देश-विदेश के लाखों अनुयायियों में स्वामी श्री पर हुए हमले और लूट की घटना पर भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते रविवार शाम को शंकराचार्य मठ में सनातन धर्म मंडल की अगुवाई में हुई बैठक में एक मत से 16 मार्च को भानपुरा नगर पूर्णता बंद करने का आह्वान किया गया था।

बता दे कि, स्वामी श्री ज्ञानानंदजी तीर्थ महाराज के साथ लखनऊ में हुई लूट एवं प्राणघातक हमले की जानकारी प्राप्त होते ही, सनातन धर्म मंडल भानपुरा की अगुवाई में तहसील कार्यालय भानपुरा में उपस्थित होकर सैकड़ों श्रद्धालु जनों ने सनातन धर्म मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद तिवारी, विधायक देवीलाल धाकड़, इंदरगढ़ मारुति आश्रम के प्रमुख स्वामी प्रकाशनाथजी महाराज आदि के साथ राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार भानपुरा एवं पुलिस थाना अधिकारी भानपुरा को ज्ञापन सौंपा गया।

स्वामी श्री पर हुए हमले के चलते सनातन धर्म मंडल के आह्वान पर रविवार 14 मार्च को श्री शंकराचार्य मठ हाल में नगर भानपुरा नगर के 56 समाज के अध्यक्षों व प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित नगर के उपरोक्त गणमान्य जनों ने स्वामी श्री के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घटी घटना पर आक्रोश एवं शोक व्यक्त करते हुए हमलावर लुटेरों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने एवं स्वामी श्री के सम्मान की लूट को लौटाने की मांग की। साथ ही यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हें पहले भी श्री मद् से स्वामी श्री की राजकीय सुरक्षा हटा लिए जाने के कारण इस तरह की घटनाएं घटित होना संभव

हुआ। यदि पूर्व में स्वामी श्री दिव्यानंद तीर्थ महाराज को एवं अन्य पूर्व में पदस्थ शंकराचार्य स्वामियों को प्राप्त राज्य की सुरक्षा वर्तमान में भानपुरा शंकराचार्य मठ की पीठ पर आसीन स्वामी श्री ज्ञानांनंद जी तीर्थ महाराज को भी राजकीय सुरक्षा हटा ली गई थी जिसे तत्काल बहाल की जाए।

470 ग्राम अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम सुनिल पाटीदार तथा एसडीओपी जावरा रविन्द्र बिलवाल के निर्देशन मे थाना प्रभारी बड़ावदा उप निरीक्षक मधु राठोर के नेतृत्व में थाना बड़ावदा व पुलिस चोकी हाटपिपलिया पुलिस टीम ने दो अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। जो सोमवार-मंगलवार की रात्री बर्डिया गोयल फन्टा ताल, जावरा रोड से गुर्जर बर्डिया से अफीम खरीद कर मन्दसौर तरफ तस्करी हेतु टीवीएस एक्सेल 100 मोपेड क्र. एमपी 14 एनडी 2965 से लेकर जा रहे थे। अफीम तस्कर कृष्णवल्लभ पिता रामचन्द्र मांदलिया जाति पोरवाल (50) व राधेश्याम पिता ओंकारलाल फ्रकया जाति पोरवाल (62) निवासी ग्राम सुठी थाना नाहरगढ़ जिला मन्दसौर से 470 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम 65 हजार रुपए की बरामद कर दोनो आरोपोयो को गिरफ्तार किया गया है।

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त चार आरोपी को कलेक्टर ने किया जिला बदर

माही की गूंज, रतलाम।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने जिले के विभिन्न पुलिस थाना अन्तर्गत चार आरोपियों को जिलाबदर किया है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर डाड ने औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत सूरज उर्फ डोंडा पिता कन्हैयालाल बैरवा निवासी शिवशंकर कालोनी, माणकचौक थाना अन्तर्गत अब्दुल रशिद पिता अब्दुल अजीज निवासी नयापुरा, थाना बाजना अन्तर्गत शांतिलाल उर्फ सकूड़ा पिता खातु निवासी ग्राम खेरदा तथा थाना ताल अन्तर्गत राजू उर्फ गब्बू पिता विजय धोबी निवासी ग्राम खारवाकला को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6-6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपीगण जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

पुजारी को न्याय दिलाने व मंदिर की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर दिया ज्ञापन

माही की गूंज, मंदसौर।

श्री वैष्णव बैरागी समाज मध्यप्रदेश, पुजारी संघ व बंजरग सेना द्वारा संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन सौंपा। इसमें जिले के ग्राम जवासिया में पुजारी द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की घटना की जांच कर पुजारी को न्याय दिलाने एवं मंदिर

की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई।

ज्ञापन में कहा कि, ग्राम जवासिया में स्थित श्री राम मंदिर में पुजारी लालदास पिता देवरामदास बैरागी पूजन करते है। मंदिर से लगी हुई कृषि भूमि पर कृषि करके पुजारी लालदास बैरागी अपने परिवार का भरण-पोषण करते है। उक्त श्रीराम मंदिर व उससे लगी कृषि भूमि सर्वे नं. 1538 जो शासन संधारित मंदिर व भूमि होकर जिसके कलेक्टर प्रबंधक है। उक्त मंदिर की भूमि पर उसी गांव के कन्हैयालाल पाटीदार ने अवैध कब्जा कर रखा है। साथ ही आए दिन पुजारी को प्रताड़ित किया जाता है। पूर्व में कलेक्टर ने अधिकारियों को आदेश दिए गए थे जिस पर अधिकारियों द्वारा 10 मार्च को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करनी चाही, किन्तु दबंगों ने उन्हें भी खाली हाथ लौटा दिया था, साथ ही उक्त दिवस पुजारी को डराया धमकाया गया। प्रताड़ता से परेशान होकर पुजारी लालदास बैरागी ने सोमवार रात में जहरीला पदार्थ खा लिया था। इस तरह की घटना आए दिन पुजारियों के साथ घटित हो रही है। जिससे समस्त वैष्णव बैरागी समाज, समस्त संत-महंत समाज, समस्त ब्राह्मण समाज, समस्त पुजारी समाज आक्रोशित है।

समाजजनों ने कहा कि, यदि सात दिवस में पुजारी पर अत्याचार करने वाले दबंगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए अन्यथा आंदोलन करने हेतु मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर बैरागी समाज प्रदेश महासचिव अजय बैरागी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष सुरेश बैरागी, प्रदेश संगठन मंत्री रामदास बैरागी, बद्रीदास बैरागी, विनय बैरागी, पशुपतिनाथ मंदिर पुजारी राकेश भट्ट, पुजारी संघ के संरक्षक महंत जितेन्द्र दास आदि उपस्थित थे।

प्रकृति का जादू संजोए खोज करने के लिए एक अभूतपूर्व स्थल है गांधी सागर अभयारण्य

माही की गूंज, मंदसौर।

गांधी सागर अभयारण्य प्रकृति का जादू देखने के लिए और खोज करने के लिए एक अभूतपूर्व स्थल है। यह मध्यप्रदेश में नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य 1974 में अधिसूचित किया गया था एवं 1983 में सरकार ने इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर दिया। गांधी सागर अभयारण्य का कुल क्षेत्रफ्ल 368.62 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। पर्यटक इस अभयारण्य में आकर कुछ समय शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। यह अभयारण्य राजस्थान राज्य से लगा हुआ है। चंबल नदी सोने पर सुहागे का काम करती है जो अभयारण्य के मध्य में से गुजरती है और इसे दो हिस्सों में बांटती है।

इस प्रकार यह नदी इस अभयारण्य को पश्चिमी एवं पूर्वी दो भागों में बांटती है, जिसमें से पश्चिमी भाग नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य आने वाले पर्यटकों के लिए निश्चित रूप से यहाँ देखने को बहुत कुछ है।

वनस्पति और जीव

अभयारण्य पूरे साल खुला रहता है। जंगली पहाड़ियों के एक अलग इलाके के साथ जंगल सूखे, मिश्रित और पर्णपाती व गांधी सागर बांध डूबने के आस-पास फ्लैट घास के मैदानों में, यह विभिन्न वन्य जीवन को देखने के प्रचुर अवसर प्रदान करता है। अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष प्रजातियां खैर (बाकिया केटेचु), सलाई, करधाई, ढवड़ा, तेंदु, पलाश इत्यादि हैं।

अभयारण्य में रहने वाली प्रमुख पशु प्रजातियां हिरण हैं, जिनमें से सबसे आसानी से चिंकारा या भारतीय गज़े, नीलगाई और सांभर हैं। इसके अलावा भारतीय तेंदुए, लंगूर, भारतीय जंगली कुत्ता, मोर, ओटर, और मगरमच्छ मौजूद हैं। अभयारण्य में पंछियों की 200 से ज्यादा प्रजातियां रह रही हैं, इनमें से कई तो दुर्लभ प्रजातियां हैं। ये वो पक्षी हैं जो विश्व में और कहीं नहीं मिलते। वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ़फ़ंड नेचर कंजर्वेशन और एमपी टाइगर फाउंडेशन के साथ मिलकर पहली बार गांधी सागर के वन क्षेत्र में बर्ड सर्वे कराया था। देश भर से आए 80 पक्षी विशेषज्ञों ने 3 दिन तक सर्वे किया था, सर्वे में 80 अलग-अलग रास्ते बनाए गए थे, हर टीम में 3-4 सर्वेयर थे।

बीती रात भी दिखा पैंथर

गांधी सागर अभ्यारण में 53 पैंथर है। जिसमें से 8 पैंथर भानपुरा की सीमा में स्थित अभ्यारण में है स्थानीय लोगो द्वारा अक्सर पैंथर को देखा जाता है। बीती रात भी गांधी सागर में पैंथर को देखा गया, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर चल रहा है फोटो के साथ रात में सफर करने वालों से सावधानी की अपील की गई है।

पुरातात्विक और धार्मिक महत्व स्थान

अभ्यारण्य में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के कई स्थान हैं। ये चौरासगढ़, चतुरभुजनाथ मंदिर, भद्राजी रॉक पेंटिंग्स, नरसिंहजर, हिंगलाजगढ़ किला, करकेश्वर मंदिर आदि हैं।

साईकिल रेली का हुआ आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ। शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ में स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत एनएसएस तथा एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का आरंभ प्राचार्य डॉ. एचएल अनिजवाल के आतिथ्य में किया गया। रैली महाविद्यालय से शुरू होकर राजवाड़ा में समापन कार्यक्रम रखा गया। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. गीता दुबे ने सभी को संबोधित किया। इस अवसर पर रैली में डॉ. अंजना सोलंकी, डॉ. रविंद्र सिंह, डॉ. संजू गांधी जैन, डॉ. मंजुला गिरवाल, प्रो. जेएस भूरिया, डॉ. गोपाल भूरिया, डॉ. वीएस मेड़ा, डॉ. प्रदीप कटारा, प्रो. दिलीप राठौर, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राजू बघेल, डॉ. मनीषा सिसोदिया, डॉ. संगीता मसानी, प्रो. जेमाल डामोर, लोहारसिंह ब्राह्मणने प्रो. मुकामसिंह चौहान, प्रो. हरिओम अग्रवाल तथा एनएसएस स्वयंसेवक मनीष गणावा, रिंकू सिंगार, देवेंद्र कहार, जितेंद्र भूरिया, महेश चौहान, सुरेश डावर आदि विद्यार्थियों ने सहभागिता की।

न्यूज ब्रीफ

6 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी जबलपुर में आयोजित ट्रायल प्रतियोगिता में

माही की गूंज, बड़वानी।

राष्ट्रीय जूनियर महिला हाकी ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन 19 मार्च से 21 मार्च तक जबलपुर में हो रहा है। जिसमे जूनियर महिला हॉकी मध्य प्रदेश के दल का चयन किया जाएगा। इस ट्रायल प्रतियोगिता में जिले से भाग लेने वाली 6 खिलाड़ियों का चयन जिला हॉकी संघ बड़वानी ने एक सप्ताह का शिविर लगाकर किया है।

हॉकी कोच मुकेश राठौर ने बताया कि, ट्रायल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सुश्री चंद्रमणि राजकुमार, सुश्री मेघा गणेश, सुश्री शिवानी बामनीया, सुश्री भाग्यश्री राकेश, सुश्री गुणाशी ईतपल गुल, सुश्री सिद्धि सुनील का चयन किया गया है। यह खिलाड़ी उक्त प्रतियोगिता में कोच मैनेजर कु. पिंकी दाऊद एवं सुमित सलूजा के नेतृत्व में भाग लेंगी।

मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्यवाही

माही की गूंज, बड़वानी।

सम्पूर्ण जिले में बुधवार को भी मास्क नहीं लगाने वालों के विरूद्ध चालान बनाकर राशि वसूलने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से बचने के लिये कई वाहन चालाको ने मार्ग बदलकर जाने की भी कोशिश की, किन्तु जगह-जगह खड़े पदाधिकारियों ने शक्ति से ऐसे लोगो को भी रोककर चालान बनाया एवं राशि वसूल कर मास्क वितरित किये । साथ ही चेतावनी भी दी कि अगली बार बिना मास्क के घर से बाहर निकलने के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माना की राशि 100 रूपये से बढ़कर 500 रूपये हो जाएगी।

गणगौर का किया स्थानीय अवकाश घोषित

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने 15 अप्रैल को गणगौर तीज के दिन सम्पूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। जिसके कारण इस दिन समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

सांसद की माता का हुआ निधन

माही की गूंज, खरगोन। क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल की पूज्य माताजी सुशीलाबाई पटेल का 85 वर्ष की आयु में बुधवार प्रात निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा आज गृह स्थान 13 ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बड़वानी से प्रात: 9 बजे निकलेगी। उनका अतिम संस्कार राजघाट पर किया जाएगा। सांसद श्री पटेल की माता सुशीलाबाई काफी समय से बीमार थी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया सुश्री सारिका घारू को ब्रांड एंबेसेडर

माही की गूंज, खरगोन। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2021 में निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जन-जागरूकता लाने के लिए शासकीय उमावि सांडिया, पिपरिया जिला होशंगाबाद की अध्यापिका सुश्री सारिका घारू को राज्य स्तरीय ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्ग विजय सिंह ने बताया कि, सुश्री घारू जिलों में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी (सेंस) से विचार-विमर्श कर सेंस की गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगी। सुश्री घारू को आवश्यक सहयोग के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए है।

हत्यारी बस आई पुलिस की गिरफ्त में

बिना परमिट और फिटनेस के आखिर कैसे सड़कों पर दौड़ रहे है वाहन

माही की गूंज वामनिया, गौरव भंडारी

विगत माह 21 फरवरी को हुई एक सड़क दुर्घटना में रतलाम जिले के नामली के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। दुर्घटना को अंजाम देने वाली बस मौके से फरार हो गई थी लेकिन प्रत्यक्ष दर्शियों और सीसी टीवी फुटेज में बस कैद हो गई थी, तब से पुलिस उक्त हत्यारिन बस की तलाश में जुटी हुई थी। बताया जा रहा है, पुलिस ने बस की काफी तलाश की लेकिन बस मालिक ने बस को छुपा दिया और दुर्घटना के मामले को रफा-दफा करने का भरसक प्रयास किया जो सम्भव नही हो पाया। बाद में पुलिस को बस ओर बस मालिक की जानकारी मिली कि, बस मेघनगर के रंभापुर क्षेत्र की है तब से लगातार बस को जप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास के बाद शनिवार को हत्यारिन बस क्रमांक एमपी 45 पी 1550 जप्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर चौकी पर लाया गया, जिसके बाद ड्राइवर को न्यायालय पेश किया गया।

चौकी प्रभारी नरेश ननमा ने बताया कि, 304 का प्रकरण बनाया गया है और परमिट नही होने के कारण बस मालिक को भी आरोपी बनाया जाएगा व बस पर यातायात नियमो के हिसाब से कार्रवाई के लिए यातायात विभाग के प्रकरण भेजा जाएगा।

बिना परमिट के दौड़ रही थी बस

साई राम बस जिस पर मेघनगर से कोटा चलना लिखा हुआ है, बस लम्बे समय से बिना परमिट के सड़क पर दौड़ रही थी जिसका खुलासा 21 फरवरी को हुई दुर्घटना के बाद हुआ। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि, बस कोटा राजस्थान तक चल रही थी। बताया जा है कि, बस का फिटनेस भी नही है। ऐसा नही की ये एक ही बस, यातायात विभाग की मिलीभगत से बिना परमिट के सड़को पर दौड़ रही है, जिले में यातायात विभाग की नाक के नीचे कई बसे बिना परमिट के दौड़ रही है।

रायपुरिया के युवा ने राजस्थान जाकर शूटिंग में दिखाए अपने जौहर

देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने का सपना

माही की गूंज, रायपुरिया। रायपुरिया निवासी युवक भूपेंद्र सिंह सिसौदिया रायफल शूटिंग के क्षेत्र में अपना व अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे है। उन्होंने अपने घर व परिवार को छोड़ राजस्थान के जयपुर स्थित द लीजेंड शूटिंग रेंज में हिस्सा लेकर जी तोड़ मेहनत कर रहे है। भूपेंद्र सिंह का सपना है कि, वह ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेकर देश के लिए पदक लाए और पूरे देश का नाम रोशन करे। हाल ही में भूपेंद्र सिंह ने 19 वी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर प्री नेशनल के लिए क्वालीफाई किया है, भूपेंद्र अपनी कोचिंग इंटरनेशनल शूटर गजेंद्र सिंह राणावत से ले रहे हैं।

मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम में सवा लाख परिवारों का गृह प्रवेश आज

माही की गूंज, खरगोन। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आज मिशन ग्रामोदय के तहत प्रदेश के सवा लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात देकर गृह प्रवेश कराएंगे। मिशन ग्रामोदय का यह मुख्य कार्यक्रम धार जिला मुख्यालय पर उदय रंजन क्लब परिसर में प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री श्री चौहान की विशेष उपस्थिति में होगा। इन सवा लाख आवासों की लागत 15 सौ 62 करोड़ रूपए है साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के साढ़े 10 हजार से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी होगा। मिशन ग्रामोदय के इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भी शामिल होंगे।

मादक पदार्थ के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही

7 लाख 79 हजार 250 रूपए के गांजे के पौधे सहित एक महिला को किया गिरफ्तार

माही की गूंज, खरगोन।

मादक पदार्थ के विरुद्ध चैनपुर पुलिस ने 7 लाख 79 हजार से अधिक की रूपए के गांजे के पौधे सहित एक आरोपिया को किया गिरफ्तार कर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। बुधवार को एएसपी जितेंद्रसिंह पंवार ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी है। चैनपुर थाना प्रभारी राबर्ट गिरवाल को 16 मार्च को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम कोटबैड़ा निवासी गोरेलाल पिता भंगडा निवासी कोटबैड़ा ने अपने नवाड के खेत में गांजे के पौधे लगाए गए है। सूचना पर थाना प्रभारी गिरवाल ने पुलिस टीम का गठन कर मुखबीर के बताएं हुए स्थान पर पहुंची, जहां पुलिस को आता देख एक व्यक्ति झाड़ियों की आड़ का फायदा उठाकर मौके से भाग गया तथा वहा खेत में काम कर रही महिला को महिला आरक्षक द्वारा पकड़ा गया। महिला से अपना नाम कंकुबाई (परिवर्तित नाम) बताया। मादक पदार्थ गांजा उगाने के लायसेंस व परमिट का पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। टीम की मदद से मादक पदार्थ गांजा के पौधो को उखाड़े गए।

खेत में 705 नग गांजे के लगाए थे पौधे

प्रेसवार्ता के दौरान बताया गया कि, खेत से गांजे के पौधो को गोरेलाल के खाली खेत मे रखकर इकट्ठे कर आरोपिया मुंदीबाई के कब्जे से गोरेलाल के खेत से गांजे के पांचों बंडल के कुल 705 नग पौधे लगाए गए थे। इनका वजन करने पर 155 किलों 850 ग्राम होना पाया गया, जिसकी कुल किमत 7 लाख 79 हजार 250 रूपए है। आरोपिया मुंदीबाई को गिरफ्तार कर किया गया। प्रकरण में फरार आरोपी गोरेलाल की तलाशी जारी है। इस कृत्य के लिए आरोपियों के विरुद्ध थाना चैनपुर में अपराध क्र 94/2021 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्यवाही में सउनि मेहबुब खान, मुकेश कुमरावत, आर रितेश, हरिनारायण, मआर पूजा एवं सहयोग में भगवानपुरा थाना प्रभारी विश्वेश्वर करील, उनि अनिल जाधव, सउनि रमेश भास्करे, नाथूराम यादव, आर आशाराम, रिंकू जाट एवं मआर रजनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सायकल रैली का हुआ आयोजन

माही की गूंज, थांदला।

आजादी की 75 वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इंकाई एवं स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठके संयुकत तत्वाधान में बुधवार को शासकीय महाविद्यालय थांदला में सायकल रैली का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में मां सरस्वती व महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संस्था प्रमुख डॉ. जीसी मेहता ने झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली शासकीय महाविद्यालय थांदला से प्रारंभ होकर मामा बालेश्वर दयाल उद्यान पर स्वतंत्रता सेनानी श्री कन्हैयालाल वैध एवं मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवन में किए कार्यो पर प्रकाश डालते हुए, सायकल रैली का समापन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. पीटर डोडियार, प्रो. सेलीन मावी, डॉ. बीएल डावर, प्रो. मीना मावी, प्रो. रेखा नागर, प्रो. मनोहर सोलंकी, प्रो. शुभदा भोसले, प्रो. देवेन्द्र धामनिया, प्रो. राजेश अहिरवार, प्रो. सीएस चौहान, प्रो. हर्षवीण राठौर, प्रो. हिमांशु मालवीया, प्रो. कंचना बास्कर, करणसिंह बामनिया, विजय मावडा, दिनेश मोरिया, दलसिंह मोरी, रमेश डामोर, विक्रम डामोर सहित बडी संख्या में महाविद्यालय के छात्रों के साथ स्कूल के बच्चें जय मोरिया, समीर मोरिया एवं सौम्य मोरिया ने भी रैली में अपनी-अपनी सायकल से सहभागिता की।

अभिकर्ताओं के साथ शाखा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

माही की गूंज, झाबुआ।

आल इण्डिया लियाफि के अव्हान पर आयोजित शाखा स्तर के प्रदर्शन में आज भारतवर्ष की प्रत्येक शाखा मुख्य द्वार पर अभिकर्ताओं के साथ शाखा के कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। जहां पर भारतीय जीवन बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा लाए गए आईपीओ का विरोध करते हुए निजी करण का भी पुरजोर विरोध किया गया। जिसमें अभिकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और निगम चेयरमैन के लिये ज्ञापन सौंपा गया। यहां पर 'बीमा धारकों के हित में अभिकर्ता मैदान में' जैसे नारे लगाए गए। उसके बाद झाबुआ लियाफी के सचिव गजानंद मेड़धवाल द्वारा एक बीमाधारकों के हितों तथा अभीकर्ताओं की 10 सुत्री मांग पत्र का वाचन किया गया।

जिसमें बीमा धारको के लिए ऋण की सुविधा पर लिए लिए जा रहे हैं ब्याज दर में कमी करना, बीमा धारकों की पूर्णावधि दावा की पॉलिसियों में बोनस दर की वृद्धि किए जाने, बीमा धारकों द्वारा दी जा रही प्रीमियम से जीएसटी का बोझ तुरंत हटाए जाने की मांग की गई। वहीं अभीकर्ताओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं में ऑनलाइन बिक्री को बंद किए जाने, अभिकर्ता के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत परिवार के समस्त सदस्यों को जोड़ने तथा अभिकर्ता के आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को मिलने वाले रिन्यूअल ग्यारंटी की धारा 44 को बीमा अधिनियम 1938 में जोड़े जाने को लेकर मांगे की गई। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के माध्यम से ज्ञापन एलआईसी के मंडल प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए दिया गया। इस अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम लियाफी झाबुआ के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के साथ जगदीश प्रसाद वैष्णव, गोविंदसिंह नायक, सुशील पाटीदार, ओपी शर्मा, प्रदीप दीक्षित, शब्बू भूरिया, ओम प्रकाश गहलोत आदि अभिकर्ता उपस्थित थे। वहीं साथ में शाखा के कर्मचारियों द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष केएस डावर, तेजप्रकाश वर्मा, एसएस पुरोहित, शीतल पंचोली, दीपक वर्मा सहित बड़ी संख्या में अभिकर्ता तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

पीजी कॉलेज परिसर में उजाड़ हो रहे गार्डन को लेकर एनएसयूआई ने जताया विरोध

माही की गूंज, झाबुआ। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के जिलाध्यक्ष विनय भाबोर ने बताया कि स्थानीय शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो जिले की अग्रणी संस्था है, बावजूद इसके यहां सुव्यवस्थित गार्डन नहीं है। कॉलेज परिसर में पूर्व में एक गार्डन था, किन्तु कॉलेज प्रशासन की लापरवाही व देखरेख के अभाव में वर्तमान में पूरी तरह से उजाड़ हो गया है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा घांस-पौधों के नाम पर लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी उक्त गार्डन में वर्तमान में एक भी जीवित पौधा नहीं है।महाविद्यालय में आने वाले छात्र-छात्राओं की जब क्लास नहीं लगती है, या खाली पेरेड में गार्डन में बैठकर अगली क्लास का इंतजार कर सके, लेकिन सुव्यवस्थित गार्डन नहीं होने से छात्र-छात्राओं को बाजार में पैदल घूमने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी होती है।

जिलाध्यक्ष भाबोर ने बताया कि कॉलेज में जब भी कोई बाहर से टीम निरीक्षण के लिए आती हैं तो प्राचार्य द्वारा बाहर से किराए के पौधे मंगवा कर कॉलेज में रखकर दिखावा कर लिया जाता है। इसके नाम पर हजारों रुपये का बिल भी लगाया जाता है, लेकिन धरातल स्थल पर कॉलेज में ना तो पौधरोपण किया जाता है और ना ही कॉलेज के एकमात्र गार्डन को संस्था प्रबंधन व्यवस्थित करवा रहा है। जिलाध्यक्ष भाबोर ने चेतावनी स्वरूप कहा कि यदि जल्द ही महाविद्यालय में उक्त गार्डन का कायाकल्प नहीं किया जाता है, तो एनएसयूआई द्वारा इस संबंध में ताला बंदी कर धरना दिया जाएगा।

देशी निमाड़ी बीजों का संकलन कर बनाया बीज बैंक

माही की गूंज, खरगोन।

पिछले 10 वर्षों से निमाड़ी बीजों के साथ-साथ देशी बीजों के भी संकलन में जुटे ग्रामीण विस्तार अधिकारी पीएस बार्चे को इंदौर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित हो रहे चार दिवसीय जैविक मेले में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया है। इस मेले में प्रदेशभर के न सिर्फजैविक किसान व व्यापारी, बल्कि जैविक अध्ययताओं व विशेषज्ञों को भी बुलाया जा रहा है। 1994 से जिले में पदस्थ बार्चे ने जिले में 500 से अधिक किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया और निरंतर वे इस कार्य में जुटे हुए है। इसके अलावा आरएईओ बार्चे ने बीज बैंक बनाने की दिशा में उनका अपना नवाचार भी महत्वपूर्ण कड़ी में से एक है। पिछले कई वर्षों से वे इस दिशा में कार्य करते हुए अब तक लगभग 12 से 15 प्रजाति की देशी किस्मों के बीज संकलन कर चुके है। बीजों के संकलन करने के पश्चात जैविक किसानों को वे संरक्षण व संवर्धन के लिए भी प्रेरित करने लगे है। आएईओ श्री बार्चे को देशी बीज बैंक और जैविक खेती के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2019 में जैव विविधता बोर्ड भोपाल द्वारा राज्य स्तरीय द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है।

निजीकरण के विरोध में बैंकों की रही हड़ताल

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

निजीकरण के विरोध में सोमवार व मंगलवार को बैंक की हड़ताल रही। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बैंकों के निजीकरण के विरोध में सारंगी की बैंकों में भी 2 दिन की हड़ताल रही, सुबह से ही बैंकों के ताले नहीं खुले, बैंकों का कामकाज 2 दिन से बंद रहा। यूनियन बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा बंद रही। बता दे कि, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के पदाधिकारियों की विज्ञप्ति के अनुसार सरकार द्वारा निजी करण प्रस्ताव संसद में पारित किया गया है, निजीकरण से आम जनता, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों को बैंकिंग सुविधा से परेशानी होगी, प्राइवेट बैंक मनमानी करने लगेंगे खातों में राशि जमा रखना अनिवार्य होगा।

ऑल इंडिया बैंक एंप्लाइज एसोसिएशन को बैंकों के निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ बैंक कर्मचारी 15 एवं 16 मार्च को दो दिनी हड़ताल पर रहे, ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका असर दिखाई दिया। जिन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं थी वह खाता धारक बैंक पहुंचकर चक्कर लगाते रहे, एकमात्र यूनियन बैंक का एटीएम भी बंद रहा जिससे खातेदार छोटी राशि निकालने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

भगोरिया पर प्रतिबंध, हाट बाजार लगेंगे

माही की गूंज, खरगोन।

स्वामी विवेकानंद सभागृह में बुधवार को कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समुह की बैठक में निर्णय लिया गया कि, जिले में कहीं भी भगोरिया का आयोजन नहीं होगा। सिर्फ पूर्व की तरह हॉट बाजार लगाए जा सकेंगे। हॉट बाजार में अब मनोरंजन के साधन जैसे झूले, नाटक-तमाशे व तंबू लगाकर इनामी प्रतियोगिता जैसे स्टॉल या दुकानें पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। इसके अलावा इन हॉट बाजारों में ढ़ोल या मांदल लेकर कोई भी नागरिक नहीं आ सकेंगे। संकट प्रबंधन समुह ने इस बात पर भी गौर किया कि, ढ़ोल-मांदल मोहल्ला या ग्राम स्तर तक सीमित लोगों द्वारा बजाया जा सकेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले व्यापारियों को भगोरिया हॉट बाजार में प्रतिबंधित किया गया है।

100 से अधिक होने पर आयोजन के लिए लेना होगी अनुमति

16 मार्च रात्रि को राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। अब जिले में खुले मैदानों पर आयोजित होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, ऐसे कार्यक्रमों की पूर्वानुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऐसे कार्यक्रम, जो किसी बड़े हॉल में होना है, वहां 200 से अधिक व्यक्ति या क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही आयोजित कर सकेंगे।

परिवार के मुखिया सहित चार की सड़क दुर्घटना में मौत, एक मासूम बालिका बची

क्षेत्रीय विधायक ने परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ से 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र सागौटा निवासी एक आदिवासी परिवार गुजरात में मजदूरी करने गया था, जो घर के मुखिया सहित सड़क दुर्घटना में 4 की मौत होकर एक बच्ची चमत्कारिक रूप से बच गई। क्षेत्रीय विधायक सुश्री कलावती भूरिया ने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी तथा आर्थिक मदद का आश्वासन दिया।

बता दे कि, रेलसिंह पिता चीडु भील अपनी पत्नी तथा तीन बच्चों को लेकर गुजरात मजदूरी के लिए गया हुआ था, विगत सप्ताह वह बाजार से घरेलू सामान खरीदने के लिए मोटरसाइकिल पर पत्नी तथा तीन बच्चों को लेकर जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिस कारण रेलेसिंह व उसकी पत्नी तथा दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची चमत्कारिक रूप से दूर गिरी जिसे हल्की चोटें आई वह जीवित बच गई। ग्राम में सूचना मिलने पर अन्य परिजन गुजरात गए तथा चारों शवों को ग्रह ग्राम लाकर अंतिम संस्कार किया। उक्त हृदय विदारक घटना जिसमें लगभग पूरा परिवार समाप्त हो गया की जानकारी क्षेत्रीय विधायक सुश्री कलावती भूरिया को मिली तो, वे शोक संतप्त परिवार से जाकर मिली तथा शोक व्यक्त किया व दुर्घटना में एकमात्र जीवित बच्ची से मिली, जिसका पालन-पोषण मृतक के भाई का परिवार कर रहा है। कलावती भूरिया ने विधायक निधि से आर्थिक मदद का आश्वासन दिया व अन्य शासकीय मदद हेतु प्रयास करने के लिए सरपंच-सचिव को निर्देशित किया।

सीसीटीवी, हैंडी केम कैमरों, ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी

भगोरिया को लेकर कानून और व्यवस्था की तैयारियों संबंधित बैठक हुई आयोजित

माही की गूंज, अलीराजपुर।

आगामी दिनों में जिले में त्योहार एवं भगोरिया शांति व सदभाव के साथ संपन्न हो इसके लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के बीच कानून और व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक आयोजित हुई। कलेक्टोरट सभाकक्ष मे आयोजित बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने की। बैठक में पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी, अपर कलेक्टर सुरेशचन्द्र वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जोबट श्यामबीर सिंह, एसडीएम अलीराजपुर श्रीमती लक्ष्मी गामड, एसडीएम सोंडवा देवकीनंदनसिंह, एसडीएम चन्द्रशेखर आजाद नगर सुश्री किरण अंजना, एसडीओपी अलीराजपुर धीरज बब्बर, एसडीओपी जोबट दिलीपसिंह बिलवाल, समस्त तहसीलदारगण, नायब तहसीलदारगण, समस्त थाना प्रभारीगण उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि, जिले में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले त्योहार एवं भगोरिया शांति पूर्ण ढंग से संपन्न हो इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाए। कोरोना के दृष्टिपत निर्देश दिए कि, हाट बाजार में दुकानों का संचालन, झूले आदि खुली जगह और निर्धारित दूरी पर लगाए जाए। भगोरिया के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जाए। जिले में लगने वाले भगोरिया के दौरान भीड के नियंत्रण हेतु पुलिस, वन सुरक्षाकर्मी, कोटवारों, सहित अन्य अमले की पर्याप्त तैनाती रहे। पूरे भगोरिया स्थल पर सीसीटीवी, हैंडी केम कैमरों, ड्रोन से नजर रखी जाए। वॉच टावर के माध्यम से पूरे भगोरिया स्थल पर सुरक्षा बल नजर रखे। मेटल डिटेक्टर से जांच के प्रबंध सुनिष्चित किए जाए। साथ ही अलाउंसमेंट की व्यवस्था सुनिष्चित की जाए। भगोरिया में आने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना सुनिश्चित कराया जाए। ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी मास्क लगाए। उन्होंने निर्देश दिए कि, भगोरिया में लगने वाले झूले-चकरी की सुरक्षा जांच की जाए। भगोरिया स्थल पर पेयजल, विद्युत सुरक्षा, एम्बुलेन्स, फायर, पानी के टैंकर आदि की पर्याप्त व्यवस्था तथा संबंधित विभाग प्रमुख उक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराए। भगोरिया हाट में किसी भी तरह का अस्त्र और शस्त्र जैसे तीर, तलवार, फालिया, बंदूक आदि प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस और बगैर वर्दीधारी पुलिस जवान भी भीड में नजर रखेंगे।

बैठक में सीएमएसओ डॉ. प्रकाश ढोके को निर्देश दिए कि, कोरोना के मद्देनजर जिले में अन्य राज्यों एवं जिलों से प्रवेश मार्गो पर थर्मल स्क्रीनिंग, तापमान की जांच, और रेपीड कोविड जांच कीट के माध्यम से आने वालों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।

बैठक पुलिस अधीक्षक भागवानी ने निर्देश दिए कि, प्रत्येक भगोरिया स्थल पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के साथ-साथ पूरे हाट स्थल पर पैनी नजर रखी जाए।

अंधे मोड़ पर सड़क किनारे दुकान लगने से लगा जाम

जननी एक्सप्रेस वाहन जाम में फंसा

माही की गूंज, आम्बुआ।

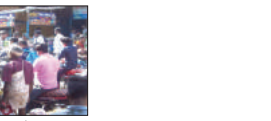

आम्बुआ कस्बे की यातायात व्यवस्था, यातायात या पुलिस विभाग की बजाय भगवान भरोसे बनी हुई है। कई बार मांग करने के बावजूद बस स्टैंड क्षेत्र में पुलिस जवानों की तैनाती नहीं की गई, जिस कारण कई बार वाहन चालको, यात्रियों तथा दुकानदारों में विवाद की स्थिति बन जाती है। वहीं मार्ग अवरुद्ध होकर जाम की स्थिति निर्मित होती रोज ही देखी जा सकती है, जाम में जननी वाहन तक कई बार फंसा देखा गया है।

हमारे संवाददाता के अनुसार आम्बुआ कस्बा का बाजार (कस्बे के अंदर) क्षेत्र कभी खुला-खुला दिखाई देता था, दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन बाजार के अंदर घूमकर आसानी से निकल जाते थे। मगर विगत 5 वर्षों से हो रहे अतिक्रमण ने बाजार की सड़कें, गलियां सकरी कर दी, जिस कारण यात्री वाहनों ने पुराने बस स्टैंड क्षेत्र को छोड़कर नया स्थान अपना लिया। इस नए बस स्टैंड क्षेत्र में भी अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई है और स्थिति पुराने बस स्टैंड क्षेत्र से भी खराब हो गई, विशेषकर साप्ताहिक हाट बाजार के दिन बस स्टैंड क्षेत्र तथा वन विभाग के पास अंधे मोड़ के पास सड़क किनारे लगने वाली दुकानों तथा अन्य दिनों में यहां संचालित दुकानों के सामने दो पहिया वाहन खड़े कर देने के कारण यातायात अवरुद्ध हो जाता है। साप्ताहिक हाट बाजार के दिन ऐसे ही जाम में जननी एक्सप्रेस वाहन फस गया जिसे बड़ी मुश्किल से ड्राइवर निकाल कर ले गया।

इस क्षेत्र में वर्षों से यातायात पुलिस की तैनाती की जरूरत महसूस की जाती आ रही है, थाना प्रांगण में होने वाली शांति समिति की बैठक हो या सुरक्षा समिति की बैठक हो समिति के सदस्यों ने बस स्टैंड क्षेत्र में पुलिस जवानों की तैनाती की मांग लगातार की है। विशेषकर साप्ताहिक हाट बाजार के दिन इनकी आवश्यकता सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी माना जा रहा है, इसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कई बार इस क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन जाती है तथा मारपीट की नौबत तक आ जाती है। नागरिकों की मांग है कि, यहां पुलिस जवान की तैनाती की जाए साथ ही जिला प्रशासन यहां हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करें।

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ नवदुर्गा स्व सहायता समूह

माही की गूंज, अलीराजपुर।

अतंराष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जिले के ग्राम बेहडवा विकासखंड सोंडवा का नवदुर्गा स्व सहायता समूह राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। उक्त समूह की पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संस्कृति जैन के समक्ष उक्त सम्मान और अपने अनुभव साझा किए। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में उक्त समूह सदस्यों के सम्मान कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती संस्कृति जैन, अपर कलेक्टर सुरेचन्द्र वर्मा, समस्त अनुविभागीय अधिकारीगण एवं विभाग प्रमुख उपस्थित थे। इस अवसर पर नवदुर्गा एसएचजी की अध्यक्ष श्रीमती नानिया सूरज, सचिव श्रीमती झमा कोटवाल, सदस्य श्रीमती काली रूमाल, श्रीमती सामली नवलसिंग, श्रीमती रूमली गणपत, श्रीमती डागरी सिलदार, श्रीमती सुडकी सूरज, श्रीमती सुरमा पुटिया, श्रीमती लया, श्रीमती साबली गमरसिंह, श्रीमती सायरी भेना, श्रीमती आन्टी मुके एवं श्रीमती बरली कालु ने अपने विचार व्यक्त किए।

बता दे कि, म.प्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिन द्वारा गठित नवदुर्गा स्व सहायता समूह को समूहों नियमों के पालन, दस्तावेजीकरण, गतिविधि संचालन और आदार्श समूह के दिशा-निर्देशो का पालन करने पर उक्त राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयन हुआ। अतंराष्ट्रीय महिला दिवस के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में नवदुर्गा एसएचजी के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती जमा ओहरिया, श्रीमती अन्ती खरत और श्रीमती नानिया दीदी सम्मानित हुई।

कलेक्टर गुप्ता ने सभी समूह सदस्यों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जिले को सम्मान दिलाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उक्त सम्मान पर कलेक्टर गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संस्कृति जैन, अपर कलेक्टर सुरेश चन्द्र वर्मा सहित समस्त अधिकारी-कर्मचारीगण, आजीविका मिशन डीपीएम इंकु बघेल सहित समस्त स्टॉफने हर्ष व्यक्त करते समूह सदस्यों को बधाई दी। कार्यक्रम में आजीविका मिशन की डीएम स्कील अनुराधा पादीदार एवं ब्लॉक टीम सदस्य राजेश भावर भी उपस्थित थे।

आमझरी में विधायक ने विद्युत डीपी का किया लोकार्पण

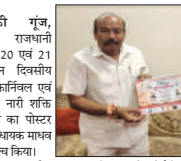

माही की गूंज, आम्बुआ। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीणों की मांग पर विधायक कलावती भूरिया ने विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफर्मर स्थापित कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आमझरी में एक डीपी का लोकार्पण विधायक भूरिया ने किया है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों का हार फूल तथा शाल श्रीफल देकर विधायक का सम्मानित भी किया। बता दे कि, ग्रामीण क्षेत्रों में एक बत्ती विद्युत कनेक्शन है जिससे सिंचाई हेतु विद्युत पम्प नहीं चल पाते हैं। इसी परेशानी के कारण ग्रामीणों ने थ्री फेज के ट्रांसफर्मर की विधायक भूरिया से मांग की थी, जिस पर विधायक ने विधायक निधि से 4 लाख 50 हजार रूपए से एक डीपी ग्राम आमझरी की तड़वी फलिया में स्वीकृत किया। इस अवसर पर डॉ. राजेंद्र सिंह राठौर, मुस्तफा तैय्यब, कमलसिंह कनेश, अमित डावर, रमेश, सुरेश, प्रेमसिंह, अनसिंह भूरिया, सरदार सिंह के साथ कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

पूर्व विधायक डावर ने एनएसपीआर हुनर कार्निवल एवं नारी शक्ति सम्मान का पोस्टर किया लॉन्च

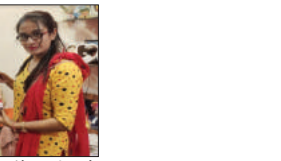

माही की गूंज, अलीराजपुर। राजधानी भोपाल में 19, 20 एवं 21 मार्च को तीन दिवसीय कार्यक्रम हुनर कार्निवल एवं रानी कमलापति नारी शक्ति सम्मान समारोह का पोस्टर जोबट के पूर्व विधायक माधव सिंह डावर ने लॉन्च किया।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एनएसपीआर एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोनिका शर्मा ने बताया कि, इसमें मध्यप्रदेश के अलावा देश भर की कई सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर किए जाने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम भोपाल स्थित पीपुल्स मॉल में किया जा रहा है। एनएसपीआर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता आमिर अल्वी द्वारा देशभर में इस कार्यक्रम को लेकर हुनरमंद लोगों को चयनित किया जा रहा हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, साथ ही भोजन एवं खरीददारी का भी इंतजाम इस कार्यक्रम में रखा गया है, जिसमें महिलाएं अपने हुनर की शक्ति का प्रदर्शन भी बखूबी करते दिखाई देंगी। इससे देश भर की महिलाओं को नई मिलेगी साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं आत्मानिर्भर मध्यप्रदेश को भी एक नया रूप मिलेगा।

आत्मनिर्भर की अवधारणा पूर्ण करने के लिए सरकार विकास कार्यों को दे गति- विधायक पटेल व भूरिया

माही की गूंज, अलीराजपुर।

आत्मनिर्भर म.प्र. की तर्ज पर आत्मनिर्भर अलीराजपुर की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए जिले में उल्लेखित विकास कार्यो को गति प्रदान की जाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमारा जिला विकास के मामले में बहुत पिछड्ड हुआ है। जिले में उच्च शिक्षा के स्तर को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने की सख्त दरकार है इसलिए जिले में कन्या महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और मेडिकल कॉलेज अविलंब खोले जाने के आदेश सरकार द्वारा दिए जाने चाहिए साथ ही इसकी संपूर्ण व्यवस्था और स्टॉफकी नियुक्ति तुरंत करना चाहिए। ये मांग भोपाल में मंगलवार को अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल और जोबट विधायक कलावती भूरिया ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को दिए पत्र में कही।

विधायक द्वय ने पत्र में बताया कि, जिले के सोंडवा, अलीराजपुर, कट्?ठीवाडा, चंद्रशेखर आजादनगर, उदयगढ और जोबट के छात्र-छात्राएं कृषि महाविद्यालय नहीं होने से अन्यत्र स्थानों पर अध्ययन हेतु जाते है। जिसके कारण आदिवासी गरीब किसानों को अपने बच्चों को पढाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझा का सामना करना पड रहा है। हमारा जिला आदिवासी क्षेत्र होकर कृषि व मजदूरी पर आधारित है। यदि यहां कृषि महाविद्यालय खोला जाता है तो उन्नत कृषि को बढावा मिलेगा और जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

कन्या महाविद्यालय की सख्त दरकार

विधायक द्वय ने पत्र में लिखा कि, जिले में अभी तक कन्या महाविद्यालय नहीं खोला गया है। जिसके कारण युवतियों को युवकों के साथ संयुक्त बैठाकर अध्ययन करने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडता है। कन्या महाविद्यालय के लिए जिले की जनता द्वारा मांग हमारे समक्ष रखी गई है। उन्होने सरकार से जिले में आगामी शिक्षा सत्र से कन्या महाविद्यालय शुरू करने की मांग की।

मेडिकल कॉलेज खोला जाना अति आवश्यक

विधायक द्वय ने सीएम को लिखे पत्र में बताया कि, जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाना अति आवश्यक है। वर्तमान बजट की सूची में आदिवासी क्षेत्र को स्थान नहीं दिए जाने से क्षेत्र की जनता और युवा वर्ग नाखुश है। क्योंकि जिले के विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर आदि स्थानों पर जाते है। जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पडता है। क्षेत्र की जनता द्वारा लगातार मांग की जा रह है कि, जिले में मेडिकल कॉलेज होने से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा और मरीजों को इलाज के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पडेगा।

अव्यावहारिक आदेशों को निरस्त करने सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, झाबुआ।

मप्र शिक्षक संघ जिला झाबुआ ने प्रदेश इकाई के आव्हान पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री,शिक्षामंत्री, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के नाम तहसीलदार झाबुआ प्रवीण ओहरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश के शिक्षक तथा शिक्षक संगठन प्रशासन तथा शासन के अव्यवहारिक व बेमतलब की योजनाओं, आदेशों से मानसिक रूप से परेशान तथा बहुत आक्रोशित है। क्योंकि प्रशासन शिक्षा, छात्र तथा शिक्षक हित में बिल्कुल गम्भीर नहीं है। अधिकारी केवल करोड़ों रुपये खर्च करने की योजनाएं बनाकर पैसों की बंदरबांट करना चाहते है। शिक्षक को सरकार तथा समाज के सामने नकारा, बेईमान साबित करना चाहते है। यदि थोड़ी भी गम्भीरता है तो वर्ष भर से बच्चे स्कूलों से दूर है, वैक्सीनेशन करके स्कूलों का शीघ्र संचालन किया जा सकता है। वर्ष भर कोरोना के कई कामों में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को वैक्सीनेशन की प्राथमिकता में टीका लगाया जा सकता था।

ज्ञापन में संगठन ने यह भी मांग की है कि आप परिणाम चाहते है तो स्कूलों में शिक्षको की पद पूर्ति करें, सर्वप्रथम पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पद पर उच्च वेतनमान ले रहे शिक्षकों को अपग्रेड कर पदनाम दें। जिसके बाद शीघ्र सीधी भर्ती के पदों पर नए शिक्षक भर्ती करें। अध्यापक संवर्ग को सेवाशर्तों के अधीन दी गई क्रमोन्नति बहाल की जाए। पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का प्रस्ताव किया जाए। अनुकम्पा नियुक्ति में डीएड-बीएड तथा पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता हटाकर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष के अंदर यह योग्यता प्राप्त करने का प्रावधान किया जाए। ज्ञापन देते समय संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कोठरी, सुभाष दुबे, रामेश्वर हरसोला, कालुसिह परमार, मोहन राठोर, विजय जैन, मानसिंह बामनिया, संजय जैन, नितीन मकवाना, मुकेश नीमा, भारतसिंह चौहान, रवि श्रीवास्तव, लच्छुसिह भूरिया व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

कोरोना से बचाव संबंधित प्रभावी कार्रवाई करें- कलेक्टर गुप्ता

माही की गूंज, अलीराजपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए कि, जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अनिवार्य है कि लापरवाही करने वालों पर पहन की कार्रवाई की जाए। मॉस्क लगाने और सोशल डिस्टेन्सींग का पालन करने के लिए आमजन को बताया जाए। नगरीय, कस्बाई और ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त निर्देशो का पालन करने संबंधित जागरूकता कार्य किया जाए। उन्होंने जिले में निर्माण कार्यों से लगी एजेंसियों के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए, निर्माण स्थलों पर तैनात श्रमिक अनिवार्य रूप से मास्क, सोशल डिस्टेन्सींग का पालन करें, यह सुनिचित कराया जाए। ऐसे स्थानों पर शिविर लगाए जाकर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाए। कंटेन्मेंट झोन स्थल की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि, जहां भी कोविड-19 पाजीटिव केस निकल रहे है संबंधित व्यक्ति की कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के कार्य को पूर्ण गंभीरता के साथ तत्काल प्रारंभ किया जाए। कोविड-19 से बचाव संबंधित पूर्व में किए गए कार्यों अनुरूप ही कार्य किया जाए, जिससे जिले में कोरोना के प्रभाव को रोका जा सकें।

स्कूलों में मास्क, सोल डिस्टेन्सींग का पालन सुनिचित हो

कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, डीईओ, डीपीसी, समस्त बीईओ, बीआरसी को निर्देश दिए कि, जिले में संचालित होने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों जहां वर्तमान में निर्देशानुसार कक्षाओं में अध्यापन कार्य हो रहा है। ऐसे विद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी अनिवार्य रूप से मास्क, सोशल डिस्टेन्सींग का पालन सुनिचित करें। स्कूल आने वाले बच्चों को कोविड-19 के संबंध में जागरूक करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेन्सींग का पालन अनिवार्य रूप से करने संबंधित निर्देश दें। उक्त निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से सुनिचित किया जाए, साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर किया जाए।

बैंकों के निजी विलयीकरण के विरोध में बैंक यूनियंस ने झाबुआ के राजवाड़ा पर किया उग्र विरोध प्रदर्शन

भारत सरकार के उक्त तानाशाही निर्णय के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

माही की गूंज, झाबुआ।

केंद्र सरकार के देष की सरकारी बैंकों के निजी विलयीकरण को लेकर संपूर्ण भारतभर में शासकीय बैंकों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा इसका उग्र विरोध किया जा रहा है। विरोध स्वरूप देषभर के करीब 40 लाख सरकारी बैंक अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल 15 एवं 16 मार्च को की गई।

इसी क्रम में झाबुआ जिले में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, बैंड ऑफ बड़ौदा, पम्र ग्रामीण बैंक, पंजाब नेषनल बैंक, महाराष्ट्र बैंक आदि शासकीय बैंकों की करीब 54 शाखाओं के 500 अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर निजी विलयीकरण पद्धति को लेकर अपना उग्र विरोध जताया गया। हड़ताल के पहले दिन 15 मार्च, सोमवार को जहां जिले की सभी सरकारी बैंकों पर ताले जड़े रहे। इन बैंकों में लेन-देन सहित अन्य सभी कार्य पूरी तरह से ठप्प रहे। वहीं दूसरे दिन भी 16 मार्च, मंगलवार को इन सभी बैंकों के अधिकारी-कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय झाबुआ पर राजवाड़ा पर एकत्रित होकर इन बैंकों के निजीकरण के खिलाफउग्र विरोध किया।

जिले में 54 शाखाएं बंद रहीं, करीब 500 करोड़ का लेन-देन प्रभावित

राजवाड़ा पर करीब एक घंटे तक इन अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से ''केंद्र सरकार हाय-हाय, भारत सरकार अपना निर्णय वापस लो-वापस लो'' नारे लगाने के साथ ही अनेक स्लोगन से लिखी तख्तीयां अपने हाथों में लेकर प्रदर्षन किया। इस दौरान सुरक्षा बतौर राजवाड़ा पर पुलिस की भी तैनाती देखने को मिली। हड़ताल कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों ने बताया कि जिले की शासकीय बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल से कुल 54 शाखाओं में लगभग 500 करोड़ का लेन-देन प्रभावित हुआ है। हड़ताल के दौरान पुरूष अधिकारी-कर्मचारियों के साथ महिला अधिकारी-कर्मचारियों ने भी अपना विरोध प्रकट किया।

झाबुआ के राजवाड़ा पर सरकारी बैंको के अधिकारी-कर्मचारियो ने निजी विलयीकरण पद्धति के खिलाफउग्र प्रदर्शन किया।

मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी

यह सांकेतिक हड़ताल यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तत्वावधान में 54 शाखाओं के बैंक अधिकारी-कर्मचारियों ने मिलकर की। अरेबिया यूनियंस के क्षेत्रीय सचिव आषुतोष मिश्रा ने चेतावनी स्वरूप कहा कि यदि दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों का निजी विलयीकरण के निर्णय पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो आगामी दिनों में अनिष्चित हड़ताल भी की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रषासन को होगी।

कोरोना को लेकर हलचल फिर हुई तेज़, आमजन में बढ़ रही लॉकडाउन की दहशत

वैक्सीन बेचने के लिए सरकार बना रही हव्वा की हो रही आमचर्चा

माही की गूंज, पेटलावद।

नगर में एक बार फिर कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। जिले सहित कई बड़े शहरों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पेटलावद में भी अब प्रशासन के द्वारा सख्ती कर दी गई है। ताकि पेटलावद सहित क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

सोमवार को एसडीएम शिशिर गेमावत के निर्देश पर पेटलावद शहर में वाहन घुमाकर डुंडी के माध्यम से नगरवासियों को सूचित किया गया है कि, नगर में मास्क को अनिवार्य रूप से लगाना होगा, साथ ही सामजिक दूरी का भी पूरा पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण ने अपने पैर फिर से पसारना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में सभी को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पेटलावद शहर में पाया जाता है, तो मौका चालान की कार्रवाई की जाएगी।

कुछ महीनों की शांति और कोरोना की वैक्सिन आने के बाद लोगो मे कोरोना का भय जाना शुरू हुआ ही था कि, फिर से प्रशासन की सख्ती और लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे है। कुछ लोग कोरोना को लेकर फिर से सतर्क होने की बात कर रहे तो, कई लोगो के बीच करोड़ो रूपए खर्च से बनी वैक्सीन को बेचने की योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। जिससे लोग कोरोना से डरकर फ्री की वैक्सीन लगने का इंतजार करने की बजाए खरीद कर वैक्सीन लगवा ले। फिलहाल तो आम जन सामाजिक दूरी को भूलकर मास्क से भी दूरी बना चुका है और सरकारी कार्यालयों में भी मास्क और सामाजिक दूरी का उपयोग न के बराबर हो रहा है, ऐसे में मंगलवार को कोरोना को लेकर नए निर्देशो का पालन कितना हो पाएगा ये देखना होगा।

थानेदार साहब पुलिस को पुलिस नहीं तो क्या कलेक्टर कहेंगे...?

पुलिस की नौकरी में चंदी चोरी कर रिटार्यड होने के बाद नाई या पत्रकार बनकर लोगों की कटिंग कर छीलने का कार्य करूंगा- चंद्रावत

माही की गूंज, झाबुआ/मेघनगर।

पुलिस की नौकरी में शायद ही कोई ऐसा पुलिसकर्मी होता होगा जो चंदी चोरी यानी मासिक हफ्ता या मामले को निपटाने में रिश्वत नहीं लेता होगा, जिसकी किसी प्रकार की कोई पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, जो सार्वजनिक है। अगर बात करें झाबुआ व अलीराजपुर जिले की तो यहां पुलिस को तरकड़े की उपाधि से पुकारा जाता है, जो भी सार्वजनिक है। पुलिस की कथनी व करनी में कितना भी फर्क हो तो भी हमारा समाज वर्दी का सम्मान ही सदैव करता आया है पर पुलिस महकमे में कई वर्दीधारियों ने वर्दी को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं कई वर्दीधारी अपनी अतिश्योक्ति के साथ ऐसा रोब झाड़ते हैं कि, उसके बारे में बात भी करे तो महज ही आश्चर्य होता है।

ऐसा ही कुछ एक मामला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी के रोब के साथ अपनी पुलिस की नौकरी में कई बार चंदी चोरी कर जेब भरने वाला थानेदार साहब अब रिटार्यड होने के बाद भी नाई या पत्रकार बनकर लोगों की कटिंग कर धन कमाने की बात अपनी अतिश्योक्ति के साथ कह डाली।

मामला मेघनगर क्षेत्र में सहकारी संस्था की दुकान से एक चार पहिया वाहन खाद्यान्न भरकर जा रहा था कि, तांदलादारा ग्राम में ग्रामीणों ने खाद्यान्न की हेरा-फेरी होने की शंका पर वाहन को रोका व पुलिस के साथ मामले की सूचना पत्रकारों को भी दी। मौके पर रम्भापुर चौकी प्रभारी हरिसिंह चुंडावत मय स्टाफके मौके पर पहुंचे, वही पत्रकार भी उक्त मामले को कवरेज करने हेतु पहुंचे। मामले की पुख्ता जानकारी हेतु मौके से पुलिस एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में ही पत्रकार दशरथ सिंह कट्ठा ने मेघनगर सीसीबी शाखा के प्रबंधक मन्नू खातेडीया से फोन कर जानकारी ले रहे थे कि, प्रबंधक ने पत्रकार को जानकारी देने के साथ ही मौके की स्थिति जानी व पूछा मौके पर कौन-कौन पहुंचे हैं, जिस पर पत्रकार श्री कट्ठा ने मौके पर रम्भापुर पुलिस व पटवारी साहब के पहुंचने की जानकारी दी। खैर उक्त खाद्यान्न समुह द्वारा बच्चो को वितरित करने हेतु ले जाया जा रहा था जिसके पत्रक पेश किए गए। लेकिन चौकी प्रभारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उर्फथानेदार साहब हरिसिंह चुंडावत को न जाने ऐसी क्या उगी की उन्हे पुलिस को पुलिस कहकर जानकारी देने के स्वरूप में पत्रकार द्वारा कही गई बात इतनी न जाने क्यों बुरी लगी कि, ग्रामीणों के समक्ष ही थानेदार ने अपनी थानेदारी का रोब पत्रकार पर झाड़ते हुए, अपनी ही चंदी चोरी की पृष्ठभूमि को प्रदर्शित कर कहने लगे कि, पुलिस-पुलिस क्या होता है, हमें हमारे पद से क्यों नहीं बुलाते, आप हमारे अधिकारी हो क्या? हम आपके नीचे कार्य करते हैं क्या? मैं सब इंस्पेक्टर हूं और कुछ माह बाद मेरा रिटायरमेंट होने के बाद मैं नाई या पत्रकार बनकर आमजनता की कटींग कर पैसे ऐढ़ कर उन्हें छिलने का कार्य करूंगा, तिलमिलाकर कहने लगे।

थानेदार की उक्त बात सुनते ही पत्रकार के साथ उपस्थित ग्रामीण भी अचंभित हो गए कि, आखिर थानेदार साहब क्या कह रहे हैं और आखिर क्या कहना चाहते हैं? जो समझ से परे ही था।

साहब नाई को तो उनकी मेहताना का पैसा मिलता है पर ग्रामीण पत्रकार बिन मेहताने के ही अपने कर्तव्य की करते हैं पूर्ति

थानेदार साहब आपकी बात पर इतना ही कहा जा सकता है कि, नाई किसी की भी जेब को काटने का काम नहीं करता है, वो अपनी हुनर व अपनी मेहनत का पैसा मेहताने के रूप में लेकर अपने परिवार का संचालन करता है और रही बात पत्रकारों की तो ग्रामीण पत्रकार, पत्रकारिता अपने शौक व अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ आमजन की आवाज बनकर बिना मेहताने के ही अपनी कर्तव्यनिष्ठा की पूर्ति करता है। वहीं जहां भी आपके जैसे चंदी चोर अधिकारी की जब-जब सच्चे पत्रकारों के कारण दाल नहीं गलती है तो उन पर आरोप लगाने में भी चूक नहीं करते हैं। आखिर में यह कहना चाहेंगे कि, थानेदार साहब नाई तो अपनी मेहनत का ही लेता है, पत्रकार अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाता है पर आप स्वयं ने यह स्पष्ट कर दिया कि, आपने अपनी पुलिसिया नौकरी में किस तरह से कटिंग करते हैं और रिटार्यड होने के बाद लोगों की कटिंग करने की मनसा आप जाहिर कर चुके हैं और आपकी इस सोच को भी समझ चुके हैं कि आगे आप क्या करोगें।

पत्रकारों ने दिया ज्ञापन

मेघनगर के पत्रकारों ने एसपी के नाम मेघनगर थाने पर पत्रकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास रम्भापुर चौकी प्रभारी हरिसिंह चुंडावत के द्वारा किया गया है के संबंध में, चौकी प्रभारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन दिया।

मामलाः भामल आजा सहकारी संस्था के प्रबंधक चैनसिंह द्वारा खाद्यान्न की हेरा-फेरी व प्रबंधक को हटाने के आदेश के बाद भी पद पर बने रहने का

स्वस्थ होने के बाद भी किया जा रहा ऐसा प्रयास की सेल्समैन नहीं ले प्रभारी प्रबंधक का चार्ज

बीमार कर्मचारी को प्रभारी प्रबंधक का चार्ज लेने के आदेश आखिर क्यों किए जारी?

माही की गूंज, खवासा/भामल। विजय पाटीदार/नारायण पालरा

प्रशासनिक व शासकीय व्यवस्था कितनी लचर है व जांच व कार्रवाई का झुनझुना पकड़ा कर किस तरह से आम लोगों को गुमराह कर भ्रष्टो को संरक्षण देकर उसे बचाने का किस हद तक सरेआम प्रयास किया जाता है यह आ.आ. सहकारी संस्था भामल में एक और उदाहरण के साथ देखा जा सकता है।

भामल आ.आ. सहकारी संस्था में बैठकर भामल व खवासा सहकारी संस्था में दूसरों के नाम से फर्जी लोन स्वयं द्वारा आहरण व खाद्यान्न की हेरा-फेरी कर गरीबों के साथ, संस्था को चूना लगाकर भ्रष्टाचार करने वाले प्रबंधक चैनसिंह राठौड़ को हर बार संरक्षण देकर संबंधित अधिकारी ने राजनेताओं के संरक्षण के साथ बचाने का प्रयास किया है। चैनसिंह द्वारा हमेशा की तरह 3 मार्च को भी अपनी पृष्ठभूमि के साथ भ्रष्टाचार को आयाम देने हेतु खाद्यान्न व खाली बारदान की दिनदहाड़े अपने निजी कार में ले जाकर हेरा-फेरी करने वाले चेनसिंह की करतूत पूर्व की तरह माही की गूंज में पूरे तथ्यात्मक रूप से 4 मार्च को उक्त मामले को उजागर किया। वही माही की गूंज में मामला उजागर होने के बाद माही की गूंज के उल्लेख के साथ सीसीबी शाखा बामनिया के प्रबंधक ने 5 मार्च को आदेश जारी कर चैनसिंह को प्रबंधक के पद से हटाने व रत्नी-कुकडिपाड़ा संस्था की सेल्समैन को प्रभारी प्रबंधक का चार्ज त्वरित लेकर सात दिनों में पूरे मामले का प्रतिवेदन पेश करने हेतु आदेश पारित किया।

रिटार्यड होने तक गठजोड़ कर भ्रष्टप्रबंधक मुख्यारी चैनसिंह प्रबंधक के पद पर करना चाहता है राज।

परंतु उक्त आदेश महज ही कार्रवाई के नाम पर ढांक के तीन पात ही साबित हो रहा है। चुंकी उक्त आदेश यह स्पष्ट कर रहा है कि, आम लोगों को गुमराह करने हेतु कार्रवाई का धकोसला कर उक्त आदेश पारित किया गया।

सेल्समैन बीमार के साथ था कोविंड से संक्रमित या फिर भी प्रभार लेने का किया आदेश जारी

कुकड़ीपाड़ा-रत्नी सेल्समैन को जारी आदेश से करीब एक माह पूर्व से बुखार, टाइफाइड की बीमारी के साथ कोविंड संक्रमण का भी असर था, बावजूद किस आधार पर कमलेश पाटीदार को त्वरित प्रबंधक के प्रभाव लेने हेतु आदेश पारित किया? यह बड़ा सवाल है।

वही उक्त आदेश में प्रबंधक का प्रभार लेने हेतु सेल्समैन कमलेश पाटीदार को आदेश पारित किया, परंतु संस्था की रत्नी-कुकडिपाड़ा दोनों दुकानों का संचालन करने हेतु किसी अन्य को सेल्समैन का पदभार संभालने हेतु आदेश पारित नहीं किया।

15 मार्च से सेल्समैन स्वस्थ होकर लोटा पर संभाल रहा सेल्समैन का ही चार्ज

यानी ये स्पष्ट होता है कि, अधिकारी प्रशासनिक व शासकीय लचर व्यवस्था का उपयोग कर बड़ी बेखुबी से भ्रष्ट चैनसिंह को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें भले ही आदेश पारित किया कि, सेल्समैन, प्रबंधक का चार्ज ले ले, परंतु सेल्समैन जब ही त्वरित प्रबंधक का चार्ज ले सकता था जब वह स्वस्थ होता या स्वस्थ होने के बाद भी उसके स्थान पर दोनों दुकान पर अन्य सेल्समैन की नियुक्ति की जाती, पर सेल्समैन की नियुक्ती नही की गई।

नतीजन सेल्समैन 15 मार्च को स्वस्थ होकर संस्था में लोटा व अपने सेल्समैन का कार्य कर कुकड़ीपाड़ा में खाद्यान्न वितरित की कर रहा है।

जातिवाद का पेत्रा फेक करना चाहता है राज

बताते हैं चैनसिंह ने भाजपाई समर्थक व खवासा मंडल के पदाधिकारी जोकि उसके समाज से ताल्लुक रखते हैं के माध्यम से, सरकार का सहयोग लेने हेतु अपने गठजोड़ लगाकर षड्यंत्र रच जातिवाद का पेत्रा फेक प्रबंधक के पद पर रिटार्यड होने के समय तक राज करना चाहता है। उसी संदर्भ ने नेता सेल्समैन के साथ ग्राम में भी चर्चा कर रहे हैं कि, कमलेश पाटीदार कैसे चार्ज प्रबंधक का ले लेगा हम देखते हैं, कह कर धमकाने जैसा प्रयास किया जा रहा है।

अब देखना है आगे क्या-क्या मामले में होता है, माही की गूंज की पूरी नजर टिकी है।

ठेके पर जनपद पंचायत पेटलावद...

पंचायतों के सरकारी काम जा रहे ठेके पर, कमीशन लेकर निपटा रहे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी

जनपद मे लगा रहता है अघोषित ठेकेदारों का जमावड़ा, कमीशन दो काम लो

माही की गूंज, पेटलावद।

देश के प्रधानमंत्री कई सेक्टर को निजीकरण करके कई घाटे में चल रहे संस्थानो को फायदे में लाने की सोच रहे है। पेटलावद विकास खण्ड की 80 पंचायतो को धनी जनपद पंचायत के अधिकारियों ने पूरी जनपद ठेके पर दे दी है। सरकार ने जन हितैषी योजनाओं और निर्माण कार्यो को आमजन तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत को माध्यम बनाया, जिससे स्थानीय लोगो को रोजगार भी मिले और विकास भी हो जाए। लेकिन जनपद पंचायत में बैठे जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए ग्राम पंचायतों में होने वाले अधिकांश कार्यो को बहारी लोगो को कमीशन लेकर निर्माण कार्य दिए जा रहे है, जनपद से होनी वाली पूरी प्रक्रिया में अधिकारी से लेकर ऑपरेटर अपना-अपना कमीशन लेकर निकल जाते है।

अघोषित ठेकेदारों का जमावड़ा लगा रहता है दिन भर

जनपद पंचायत की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि, कार्यालय में दिन भर अघोषित ठेकेदारो का जमघट लगा रहता है और विकास खण्ड की ग्राम पंचायतो में काम करने के लिए प्रकरण बनाकर अपने हिसाब से अधिकारियों से मिल कार्य स्वीकृत कराने की जुगाड़ में लगे रहते है। जनपद कार्यालय का आलम ये है कि, यहां काम करने वालो की संख्या से भी ज्यादा अघोषित ठेकेदार जिसमे कई पत्रकार और नेता सुबह से टिके रहते है, ग्रामीण इलाकों से आने वाले कई शिकायतकर्ता इनके चंगुल में फसकर उस पंचायत में कार्य लेने का जरिया तक बन जाते है। कार्रवाई की आस में पहुंचे ग्रामीणों का काम हो न हो इन अघोषित ठेकेदारो के नए काम का जुगाड़ होता है। जनपद पंचायत का माहौल देखकर कहा जा सकता है कि, पूरी जनपद का निजीकरण होकर ठेके पर चली गई है जहां सरकार की तनख्वा खा रहे कर्मचारियों के हिसाब से नही, ठेकेदार के बाटे जा रहे कमीशन के हिसाब से काम होता है।

कोई खबर लगे या शिकायत हो तो उनको भी काम ऑफर होता है

जनपद पंचायत सीईओ से लेकर जनपद में बैठे हर कर्मचारी और उपयंत्री तक का काम के हिसाब से कमीशन फिक्स है, जो फाइल के साथ-साथ अघोषित ठेकेदारो को एडवांस खर्च करना पड़ता है, प्रकरण स्वीकृति होने से लेकर मस्टर निकलने और बिल भुगतान करने तक लेन-देन होता है। मौके पर क्या हो रहा, कैसे हो रहा है उससे कोई मतलब नही। इतना ही नही कोई लंबी शिकायत और समाचारों के निराकरण के एवज में शिकायतकर्ता और पत्रकारो को पंचायतो में रोड़, चैक डेम, सदुर सड़क, पुलिए निर्माण जैसे कार्य करने के प्रभोलन दिए जाते है, जिसके लिए जनपद पेटलावद में बनी कमीशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। गूँज के पास ऐसे एक दो नही कई साईडो पर कार्य करवा रहे अघोषित ठेकेदारो के फोटो और वीडियो उपलब्ध है जिनसे ग्राम पंचायत के कार्यो में ठेकेदारी प्रथा की पुष्टि होती है।

फर्जी बिलो की भरमार, बिना साधन सामान वाली कई एजेंसियों के वेंडर जुड़े

जनपद की आड़ में फर्जी बिलो के भुगतान का बड़ा खेल भी चल रहा है। यहां कई ऐसी फर्जी फर्म के वेंडर जुड़े हुए है, जिनके पास जीएसटी नम्बर है और इसी के दम पर ये एजेंसियां बिना कोई कार्य और मटेरियल सप्लाई किए बिना कमीशन पर अपने बिल देकर भुगतान लेती है। लेकिन वास्तव में ऐसी फर्मो के द्वारा दिए गए बिलो में बताए हुए कार्य और सप्लाई की गई सामग्री का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नही है। अघोषित ठेकेदार ऐसी फर्मो के बिल भुगतान प्राप्त करने के लिए लगाते है जिनसे उनको भुगतान लेने में दिक्कत नही हो। विगत एक वर्ष में जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा ग्राम पंचायत को हुए भुगतान के बिलो की जांच की जाए तो पता लगेगा कि, ऐसी कई फर्म है जो बताई हुई पंचायत से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से पंचायत द्वारा कभी न तो माल खरीदा गया न ही पंचायत उन फर्मो को जानती है। जो बिल अघोषित ठेकेदार द्वारा दिए जाते है उन्हें आंख बंद करके स्वीकृत कर दिए जाते है, तो ट्रेक्टर संचालको द्वारा भी धड़ाले से रेत, गिट्टी और मोरम सप्लाई के बिल लगाए जा रहे है जिनकी कोई रॉयल्टी की रसीद नही है। बिलो के भुगतान की बारीकी से जांच होती है तो जनपद के निजीकरण की खबर की पुष्टि प्रमाण सहित हो जाएगी।

कुरान की आयते हटवाने की अपील करने पर वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज करने की उठी मांग

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अग्रवान

मुस्लिम महासभा ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफकेस दर्ज करने को लेकर सीएसपी को आवेदन सौंपा है। आवेदन में मुस्लिम महासभा ने बताया कि, वसीम रिजवी ने मुस्लिम समाज के धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ में से 26 आयतों को हटाने के लिए, देश में अस्थिरता लाने व सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया है। वसीम रिजवी न तो मुस्लिम धर्मगुरु है और न ही कुरान शरीफके ज्ञाता। उसके द्वारा ये बात करना बेमानी है। जिस पर सीएसपी ने महासभा को आश्वासन दिया है कि, जल्द इस मामले को देखकर एफआइआर दर्ज की जाएगी।

इस दौरान काजी-ए-शहर मंदसौर जनाब आसिफउद्दाह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मो. हनीफशेख, अंजुमन सदर शकील अली, एडवोकेट अनीस मंसूरी, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग शहर अध्यक्ष साबिर हुसैन शाह, अंजुमन सेक्रेटरी फिरोज मेव और मुस्लिम महासभा जिलाध्यक्ष आमिर पठान, मुस्लिम महासभा के आमील चौधरी, माजिद चौधरी, अनिस खान, युसूफ आगवान, तौसीफ खान, अकरम जाफ्री, इमरान शाह आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुस्लिम समाज ने वसीम रिजवी का पुतला जलाया

वहीं जिले की भानपुरा अंजुमन कमेटी द्वारा वसीम रिजवी का जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। इसमें कहा गया कि, वसीम रिजवी ने कुराने पाक की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पीआइएल के खिलाफदेशभर के मुसलमानों में आक्रोश है। इसे लेकर भानपुरा में भी अंजुमन कमेटी द्वारा शहर काजी इमरान अली, सदर जाफर खान के नेतृत्व में वसीम रिजवी का पुतला जलाया गया और नारेबाजी की गई। इस दौरान अंजुमन कमेटी के सदस्य मस्जिदों के इमाम व मुस्लिम समाज के कई लोग मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422